



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2016/फाल्गुन 25, 1937

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2016/PHALGUNA 25, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: विएतनाम और थाईलैंड मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सभी प्रकार की डिजीटल वर्सेटाईल डिस्क - रिकार्डेबल (डीवीडी-आर)" के आयातों पर पाटन-रोधी निर्णायक समीक्षा जांच (एस एस आर) ।

फा. सं. 15/01/2015-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने दिनांक 5 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/16/2009-डीजीएडी द्वारा मलेशिया, थाईलैंड और विएतनाम मूल की अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार की डिजीटल वर्सेटाईल डिस्क - रिकार्डेबल (डीवीडी-आर) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की थी। इसका प्रारंभिक परिणाम प्राधिकारी दिनांक 13 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 14/16/2009-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया था तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 48/2010-सीमा शुल्क द्वारा अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया गए थे। प्राधिकारी का अंतिम परिणाम दिनांक 2 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/16/2009-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया था जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

2. प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 98/2010-सीमा शुल्क द्वारा मलेशिया, थाईलैंड और विएतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे। ये निश्चयात्मक शुल्क, अनन्तिम शुल्क की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात् 11 अप्रैल, 2015 तक वैध थे। बाद में घरेलू उद्योग के अनुरोध पर प्राधिकारी ने दिनांक 16 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/5/2012-डीजीएडी द्वारा विएतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ मध्यावधि समीक्षा शुरू की थी तथा प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 को जारी अंतिम परिणाम के आधार पर सीमा शुल्क की दिनांक 31 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 34/2013 द्वारा विएतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्क बढ़ा दिए गए थे।
3. मेसर्स मोजन बेयर इंडिया लिमिटेड जो कि संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख घरेलू विनिर्माता है, ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष विधिवत् अधिप्रमाणित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में मलेशिया, थाईलैंड और विएतनाम मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने अथवा पाटन की पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग का परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है तथा उपरोक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित केवल डिजिटल वर्सेटाईल डिस्क - रिकार्डेबल (डीवीडी-आर) के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखने तथा उसको बढ़ाने की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
4. घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा शुरू करने की अपनी याचिका में निवेदन किया है कि डीवीडी-आरडब्ल्यू के आयात जो कि पाटन-रोधी शुल्कों के अध्यधीन हैं, काफी अधिक कीमतों पर हो रहे थे और इसलिए वे घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं कर रहे थे। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि याचिकादाता का डीवीडी-आरडब्ल्यू का उत्पादन, डीवीडी-आरडब्ल्यू के उत्पादन और बिक्रियों की तुलना में अत्यधिक कम है, इसलिए डीवीडी-आरडब्ल्यू के आयात पाटन और क्षति होने के रूप में उसके लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य, हांग कांग और चीनी ताईपेई से संबंधित निर्णायक समीक्षा में व्यापक जांच करने के बाद प्राधिकारी ने शुल्क लगाने/बढ़ाने के कार्य-क्षेत्र से डीवीडी-आरडब्ल्यू बाहर कर दिया था, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि इस उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही थी और इस उत्पाद के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई सन्निकट संभावना नहीं थी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से भी डीवीडी-आरडब्ल्यू को बाहर निकाल दिया है।
5. ऐसे शुल्क मलेशिया, विएतनाम और थाईलैंड के खिलाफ लगाए गए थे। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के कोई आयात नहीं हुए थे। याचिकादाता ने मलेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए प्राधिकारी ने इस समीक्षा को केवल थाईलैंड और विएतनाम पर शुल्क लगाने तक ही सीमित करने का निर्णय लिया था और मलेशिया को निर्णायक समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था।
6. तदनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किए गए अधिप्रमाणित आवेदन पत्र के आधार पर तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 27 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/01/2015-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है, ताकि थाईलैंड और विएतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित केवल "डिजिटल वर्सेटाईल डिस्क - रिकार्डेबल (डीवीडी-आर)" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के संबंध में शुल्कों को निरंतर लागू रखे जाने समीक्षा की जा सके और इसकी जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
7. केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2015 की अधिसूचना संख्या 12/2015-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की वैधता को बढ़ा कर 11 अप्रैल, 2016 कर दिया गया है।
8. मौजूदा समीक्षा में केवल संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच के सभी मुद्दे शामिल हैं।

ख. क्रिया-विधि

9. प्राधिकारी ने इस जांच के संबंध में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया है :-

- (1) नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के बारे में नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया गया था और जांच शुरू करने की अधिसूचना और याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां भी संबंधित दूतावासों को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराई गई थीं कि वे अपने देशों में संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों और निर्यातकों को उन्हें उपलब्ध करा दें।
- (2) प्राधिकारी ने नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां और याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां प्रेषित की थीं और उन्हें चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा देने का अवसर प्रदान किया था :-
 - (क) मेसर्स जेट-टेक हाई-टेक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - (ख) मेसर्स रिटेक विएतनाम कंपनी लिमिटेड, विएतनाम
- (3) संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई निवेदन किया है। संबद्ध देशों की सरकारों से भी कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- (4) प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना और याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति अग्रेषित की थी और उन्हें परामर्श दिया था कि वे पत्र के जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से उन्हें अवगत करा दें :-
 - (क) राशि पेरीफेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
 - (ख) डायनेमिक ओवरसीज
 - (ग) जश इंटरनेशनल
 - (घ) हेनिक्स ओवरसीज
 - (ङ) आदित्य इंटरप्राइजिस
 - (च) वीलाईन मीडिया लिमिटेड
 - (छ) हिमालयन टाईम्स प्राईवेट लिमिटेड
 - (ज) एलाईड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड
 - (झ) राणा पेरीफेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
- (5) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली के उत्तर देने के माध्यम से कोई निवेदन नहीं किया है।
- (6) जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तुओं के अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों, (1) यूरो मल्टीवीजन लिमिटेड और (2) जूपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड को भी भेजी गई थी। इन पक्षकारों में से किसी ने भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (7) जिन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी का न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, प्राधिकारी द्वारा उन्हें सहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना है।

- (8) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह क्षति अवधि (2010 – मार्च 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013) जिसमें जांच अवधि (अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014) शामिल है, के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात के आंकड़ों के व्यौरों की व्यवस्था करें।
- (9) प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त, हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुले उपलब्ध करा दिए हैं।
- (10) प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है और अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग को उससे होने वाली क्षति, यदि कोई है, को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (11) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 1 फरवरी, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था जिसमें केवल घरेलू उद्योग और उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस मौखिक सुनवाई में केवल घरेलू उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वह मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी द्वारा जितना उन्हें प्रासंगिक समझा गया है, प्रमाणों के समर्थन से उनको रिकार्ड में लिया गया है।
- (12) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की, प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, उतनी जांच की गई है तथा उनका निदान इस जांच में किया गया है।
- (13) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा है, संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है तथा उसे गोपनीय सूचना माना है और उसे प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान करें।
- (14) जहां कहीं भी यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में अनिवार्य तथ्यों के रूप में रिकार्ड किया है तथा ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है।
- (15) इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की परिचायक है और प्राधिकारी ने इसे नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना है।
- (16) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 31 सितंबर, 2014 तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच की अवधि में अप्रैल 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तथा जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।
- (17) जांच अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर = 60.61 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र और समान वस्तु

10. जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 में नोट किया गया है, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में सभी प्रकार की "रिकार्डएबल डिजिटल वर्सेटाईल डीवीडी-आर, डीवीडी+आर और मिनी डीवीडी-आर" शामिल होंगी (जिन्हें आगे संबंध वस्तुएं कहा गया है)।

11. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उपरोक्त विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र की संपुष्टि की है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

12. याचिकादाता ने निवेदन किया है कि देश में विचाराधीन उत्पाद के चार अन्य ज्ञात उत्पादक हैं – यूरा मल्टीवीजन लिमिटेड, जूपीटर इंटरनेशनल और नेक्सट स्टार डिजिटल। तथापि, याचिकादाता, मेसर्स मोजर बीयर इंडिया लिमिटेड का जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में 87% से भी अधिक का योगदान है और इसलिए वह घरेलू उद्योग बनता है तथा इस जांच के प्रयोजनार्थ आधार के आवश्यकता को पूरा करता है। किसी भी अन्य निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है अथवा उसके घरेलू उद्योग होने का खंडन नहीं किया है। चूंकि मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई खंडन नहीं किया है और आवेदक उत्पादक का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में प्रमुख अंशदान बनता है, प्राधिकारी का यह विचार है कि याचिकादाता का निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का आधार है और वह पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।

ङ. हितबद्ध पक्षकारों के अन्य निवेदन

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के याचिकादाता को छोड़ कर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस निर्णायक समीक्षा जांच को शुरू करने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए निवेदनों की जांच, इस प्रकटन विवरण में संबंधित भागों में की गई है।

च. मौजूदा पाटन का निर्धारण और पाटन के निरंतर बने रहने और पुनरावृत्ति होने की संभावना**च. 1 कानूनी स्थिति**

14. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुच्छेद 9 क (3) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“इस धारा के अंतर्गत लगाया गया शुल्क जब तक रद्द नहीं कर दिया जाता है तब तक ऐसा शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार का उसकी समीक्षा में ऐसा विचार है कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, वह ऐसे शुल्क को लागू करने की अवधि को समय-समय पर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक आगे बढ़ा सकती है और ऐसी बड़ी हुई अवधि ऐसा विस्तार करने की तारीख से प्रभावी होगी।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि जहां उपरोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले समीक्षा जांच शुरू की गई और ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, वहां ऐसी समीक्षा परिणाम के लंबित होने पर पाटन-रोधी शुल्क निरंतर लागू रहेगा, लेकिन उसकी ऐसी बड़ी हुई अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

15. तदनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में इसकी जांच की जानी है कि –

- क्या पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बाद पाटन निरंतर जारी रहता है, यदि हां, तो क्या उसके निरंतर जारी रहने की संभावना है।
- ऐसे मामलों में जिनमें पाटन निरंतर जारी नहीं रहता है, क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है और यदि हां, तो क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निरंतर होते रहने की संभावना है।

- ऐसे मामलों में जिनमें घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है, क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है।

16. इसलिए प्राधिकारी ने पहले इसकी जांच की है कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है और क्या शुल्कों को रद्द कर दिए जाने पर पाटन के निरंतर होते रहने अथवा उसकी आवृत्ति होने की संभावना है।

च. 2 पाटन, यदि कोई है, के निरंतर रहने की जांच, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की क्रिया-प्रणाली

च. 2.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. याचिकादाता घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह निवेदन किया है कि उसने थाईलैंड और विएतनाम के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए थे। प्रकाशित स्रोतों से भी कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, वह थाईलैंड और विएतनाम के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त नहीं कर सका है। इसको ध्यान में रखते हुए थाईलैंड और विएतनाम से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना आधार पर प्रमुख कच्चे माल की लागत के आंकड़ों के संतुलित आधार पर की गई है। चूंकि इस अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस द्वारा सूचित की गई आयात कीमतें अधिक थीं, इसलिए घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर प्रमुख कच्चे माल अर्थात् पोलिकाबॉनिक की कीमतों और खपत के मानदंडों को अपनाया गया है।

च. 2.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. इस संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई निवेदन नहीं किया है।

च. 2.3 थाईलैंड और विएतनाम में सामान्य मूल्य का निर्धारण

19. पाटन के उपरोक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी क्योंकि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के ऐसा कोई प्रत्यक्ष और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं था जिससे इस चरण में उचित तुलना की जा सके। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान पाटन के साथ-साथ पाटन के निरंतर बने रहने अथवा पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना, जैसी भी स्थिति हो, हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध देशों से सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। चूंकि थाईलैंड और विएतनाम में किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने उन देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के बारे में कोई सूचना अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने विवश हो कर उपलब्ध उत्तम तथ्यों जिनमें पाटन-रोधी करार के अनुबंध- 2 के पैरा 1 के अनुसार घरेलू उद्योग की याचिका में निहित सूचना भी शामिल है, के आधार पर इन देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

20. तदनुसार प्राधिकारी ने भारत में याचिकादाता घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर उपलब्ध उत्तम सूचना के रूप में प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और देश में प्रचलित उत्पादन लागत के लिए उचित समायोजन करने और उचित लाभ के लिए विधिवत् प्रावधान करने के बाद थाईलैंड और विएतनाम में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार विएतनाम और थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | विएतनाम | थाईलैंड |
|--|----------|----------|
| | रूपए/अदद | रूपए/अदद |
| पैकेजिंग सामग्री की लागत सहित घरेलू कीमत के अनुसार कच्चे माल की लागत | *** | *** |
| उपयोज्यताएं | *** | *** |
| ब्याज सहित परिवर्तन लागत/एसजीए | *** | *** |
| लाभ | *** | *** |
| सीएनवी (रूपए/अदद) | *** | *** |
| सीएनवी यूएस \$/000 अदद | *** | *** |
| विनिमय दर यूएस \$ 1 = | 60.81 | 60.81 |

च. 2.4 निर्यात कीमत

21. चूंकि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया जा सके, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमतों का निर्धारण, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात आंकड़ों के अनुसार भारत को आयातों की सीआईएफ कीमत के आधार पर किया है, जिसके लिए उपलब्ध उत्तम सूचना के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्ययों, कमीशन, निर्यातक देश में अंतरदेशीय परिवहन, क्लीयरिंग प्रभारों और बैंक प्रभारों के लिए लागू समंजन किया गया है, ताकि कार्यगत स्तर पर निर्यात कीमतों को तय किया जा सके। तदनुसार इन देशों से तय की गई निर्यात कीमत निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | थाईलैंड | विएतनाम |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| आयातों की मात्रा | लाख अदद | 52.50 | 22.01 |
| आयातों का सीआईएफ मूल्य | लाख रूपए | 226.31 | 97.99 |
| सीआईएफ कीमत | रूपए/अदद | 4.31 | 4.45 |
| समुद्री भाड़ा | रूपए/अदद | 0.06 | 0.07 |
| समुद्री बीमा | रूपए/अदद | 0.01 | 0.01 |
| एफओबी निर्यात कीमत | रूपए/अदद | 4.24 | 4.38 |
| पत्तन व्यय @ 0.50 % | रूपए/अदद | 0.02 | 0.02 |
| अंतरदेशीय भाड़ा @ 0.50 % | रूपए/अदद | 0.02 | 0.02 |
| संचालन प्रभार @ 1% | रूपए/अदद | 0.04 | 0.04 |
| क्लीयरिंग प्रभार @ 1% | रूपए/अदद | 0.04 | 0.04 |
| बैंक प्रभार | रूपए/अदद | 0.04 | 0.04 |
| निबल निर्यात कीमत | रूपए/अदद | 4.07 | 4.20 |
| विनिमय दर - यूएस \$ | भारतीय रूपए | 60.80 | 60.80 |
| निबल निर्यात कीमत | यूएस \$/000 अदद | 66.96 | 69.16 |

च. 2.5 पाटन मार्जिन

22. उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य-प्रणाली के अनुसार संबद्ध देशों के लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना, कारखाना गत लागत स्तर पर संबंधित निर्यात कीमत के साथ की गई है, जैसा कि उपरोक्त पैराओं में निर्धारित किया गया है, ताकि संबद्ध देशों में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन तय किया जा सके जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | थाईलैंड | विएतनाम |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| सामान्य मूल्य | यूएस \$/000 अदद | *** | *** |
| निबल निर्यात कीमत | यूएस \$/000 अदद | 66.96 | 69.16 |
| पाटन मार्जिन | यूएस \$/000 अदद | *** | *** |
| पाटन मार्जिन | % | *** | *** |
| पाटन मार्जिन | % सीमा | 70-80% | 60-70% |

23. उपरोक्त मूल्यांकन से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान थाईलैंड और विएतनाम से भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर डीवीडी-आर का निरंतर प्रवेश हो रहा है तथा हालांकि ऐसे आयातों की मात्रा कम है, लेकिन पाटन मार्जिन बहुत अधिक

है। इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के पाटन के निरंतर बने रहने अथवा उसकी आवृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

छ. पाटन के निरंतर बने रहने अथवा पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. याचिकादाता घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि इस समीक्षा में जांच के अंतर्गत शामिल देशों के अतिरिक्त विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटनका इतिहास रहा है और प्राधिकारी ने विगत में इस उत्पाद के खिलाफ अनेक जांच की है जिनके परिणाम स्वरूप पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए हैं, जो कि निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | जांच | जांच की अवधि | देश | पाटन मार्जिन % | पाटन-रोधी शुल्क (यूएसडी 1000 अदद) |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | पहली जांच | अप्रैल, 2006 से जून, 2007 तक | चीन जनवादी गणराज्य | 64.72 | 68.11-48.11 |
| | | | हांग कांग | 62.96 | 66.72 |
| | | | चीनी ताइपेई | 63.50 | 45.63 |
| 2 | दूसरी जांच | अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक | मलेशिया | 34.05 | 35.92 |
| | | | थाईलैंड | 22.51 | 25.98 |
| | | | विएतनाम | 64.09 | 29.75-50.51 |
| 3 | दूसरी जांच की मध्यावधि समीक्षा | अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक | विएतनाम | 105-115% | 73.01 |
| 4 | पहली जांच की निर्णायक समीक्षा | अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक | चीन जनवादी गणराज्य | 100-120% | 36.67 |
| | | | हांग कांग | - | 36.67 |
| | | | चीनी ताइपेई | 25-35% | 22.39 |

25. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि विगत में सभी जांच में डीवीडी पर विचार किया गया था और उनमें इन देशों से अत्यधिक पाटन होने और इस तथ्य का पता लगता है कि विश्व के उत्पादकों द्वारा पाटन किया जा रहा है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इन निर्यातकों को भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने के अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे जिससे घरेलू उद्योग बाजार का हिस्सा समाप्त हो जाएगा।

26. इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से रिटेक के पास ताईवान, चीन और विएतनाम में उत्पादन की स्थापित सुविधाएं हैं। पाटन-रोधी शुल्क लगाने के बाद और ताईवान से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना को ध्यान में रखते हुए रिटेक ने विएतनाम में कुछ विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की थी और विएतनाम से पाटन करना शुरू कर दिया था। रिटेक ने ताईवान से आयातों के संबंध में पहली जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया था। तथापि, बाद में जब निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विएतनाम के संबंध में जांच शुरू की थी तो रिटेक ने उत्तर प्रस्तुत किया था तथा जांच में पूरी सहभागिता की थी तथा विएतनाम से आयातों के संबंध में रिटेक पर अत्यधिक कम मात्रा में पाटन-रोधी शुल्क लगाया था। इस कंपनी ने विएतनाम से गहन पाटन दिया था और विएतनाम से निरंतर निर्यात किया था। इस जांच अवधि के दौरान ताईवान और चीन से आयात बहुत कम बने हुए थे। घरेलू उद्योग ने गहन पाटन को ध्यान में रखते हुए विएतनाम से आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा करने की याचिका प्रस्तुत की थी। कंपनी ने मध्यावधि समीक्षा का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने व्यापक जांच करने के बाद विएतनाम से आयातों पर यूएस डालर 73.01/000 अदद की दर से बड़े हुए शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो कि बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया था।

27. जब नवंबर, 2014 में ताईवान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी, तो मेसर्स रिटेक जिसके विएतनाम और ताईवान में दो संयंत्र हैं, ने उक्त जांच में भाग नहीं लिया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विएतनाम की कंपनी, ताईवान कंपनी की निजी सहायक कंपनी है, याचिकादाता द्वारा विएतनाम संयंत्र के लिए रिटेक ताईवान द्वारा अधिप्राप्त किए जा रहे कच्चे माल के मूल्यांकन, व्याज लागत और अन्य लागत के संबंध में अत्यधिक मुद्दे उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त

यह तर्क दिया गया था कि विएतनाम की लेखा बहियों में अत्यधिक ऊपरी लागत को हिसाब में दर्ज नहीं किया जा रहा था और इन्हें ताईवान की लेखा बहियों में दर्ज किया जा रहा था।

28. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच में निर्णय लिया था और ताईवान से आयातों के खिलाफ लगाए गए शुल्क को यूएस डालर 65.63/000 अदद से अत्यधिक कम करके यूएस डालर 22.32/000 अदद कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप विएतनाम से अत्यधिक मात्रा में निर्यात ताईवान की ओर उन्मुख हो गए थे, जैसा कि इस जांच में जांचअवधि पश्चात के आंकड़ों से देखा जा सकता है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

| निम्नोक्त से आयाता | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि | जांच अवधि पश्चात |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|------------------|
| विएतनाम | लाख अदद | 204.93 | 258.39 | 121.50 | 22.01 | 14.67 | - |
| थाईलैंड | लाख अदद | 1.49 | - | 0.10 | 10.50 | 7.00 | 54.93 |

29. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इन परिस्थितियों में यदि विएतनाम से मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो कंपनी फिर से विएतनाम से पाटन करना शुरू कर देगी क्योंकि ताईवान के खिलाफ शुल्क लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान विएतनाम से कंपनी जिस कीमत पर वस्तुओं के निर्यात कर रही थी, से साफ पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उसी कीमत पर कंपनी पाटन करेगी।

30. इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं। कुछ समाचार रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि रिटेक की अकेले विएतनाम में लगभग 20 मिलियन अदद प्रति माह उत्पादन करने की क्षमता स्थापित है। थाई ट्रेड सेंटर की वेबसाइट जो कि थाईलैंड (डीआईटीपी) की वेबसाइट है, पर उपलब्ध सूचना का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि थाईलैंड में प्रमुख डिस्क उत्पादक, डार्इनटेक डिस्क प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड की डीवीडी का 0.8 मिलियन अदद प्रति मास उत्पादन करने की विनिर्माण करने की क्षमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि थाईलैंड और अन्य देश में अन्य उत्पादक, जेट थाई हार्ड-टेक कंपनी लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में अपने उत्पादन आधार का विस्तार कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि इस उत्पाद की वैश्विक मांग में गिरावट को ध्यान में रखते हुए इन देशों में अत्यधिक फालतू क्षमताएं विद्यमान हैं और यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो वे अत्यधिक मात्रा में उनका पाटन करने में समर्थ होंगे।

31. याचिकादाता घरेलू उद्योग ने आगे यह निवेदन किया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है, तो उससे ऐसा स्पष्ट पता चलेगा कि विगत में विभिन्न देशों की पाटन करने की सुसंगति पद्धति रही है। यदि एक सेट के देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो किसी अन्य सेट के देशों से पाटन शुरू हो जाता है। पाटन में ऐसे अंतरण से यह स्पष्ट पता चलता है आयातक जानबूझ कर और बड़ी ईमानदारी से पाटन कर रहे हैं और इसलिए यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है तो पाटन की पुनरावृत्ति होगी।

छ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार की ओर से कोई निवेदन नहीं किया गया है।

छ. 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि विगत भाग में उल्लेख किया गया है, थाईलैंड और विएतनाम से डीवीडी-आर के आयात के मामले में पाटन का निरंतर जारी रहना सिद्ध हो गया है, हालांकि संबद्ध देशों सहित अनेक देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के कारण जांच अवधि में इन देशों से आयातों की मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई है। चीन जनवादी गणराज्य, हांग कांग और चीनी ताईपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इस उत्पाद पर, इन देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के परिणाम के आधार पर पाटन-रोधी शुल्क बढ़ा दिए गए हैं और ये वर्ष 2019 तक लागू रहेंगे। तथापि, यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के बाद आयातों में विएतनाम से ताईवान की ओर अत्यधिक स्थानांतरित हो गए हैं, जो कि ऐसा उक्त देश के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच में ताईवान पर लगाए गए शुल्क को कम करने के समय हुआ है।

34. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विश्व बाजार में इस उत्पाद की मांग में अत्यधिक गिरावट आई है जिसके कारण विभिन्न देशों में इसकी कुछ क्षमताएं बेथी/निष्क्रिय हो गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताओं के बारे में कुछ सूचना प्रदान की है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि इन देशों में इस उत्पाद की बेथी क्षमताओं की उपलब्धता होने तथा विश्व बाजार में मांग में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए ऐसी सुदृढ़ संभावना है कि इन वस्तुओं का भारत में पाटित कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में निर्यात होने लगेगा।

35. इस संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष कोई वस्तुगत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन अभी भी अधिक है, हालांकि उसकी मात्रा में गिरावट आई है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि इन देशों से मात्रा में अंतरण होगा तथा इसके अतिरिक्त यह ध्यान में रखते हुए कि इस उत्पाद के लिए विश्व बाजार में मांग और पूर्ति में अत्यधिक विषमता है, प्राधिकारी का यह विचार है कि यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है, तो संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की स्पष्ट और सन्निकट संभावना है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की निर्धारण और घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

ज. 1 कानूनी स्थिति

36. जैसा कि विगत भाग में बताया गया है, क्षति की जांच करने के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह जांच करने की आवश्यकता होती है कि -

- क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति हो रही है और यदि हां, तो क्या यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना बनी रहेगी अथवा
- ऐसे मामलों में जिनमें घरेलू उद्योग को कोई निरंतर क्षति नहीं हुई है, क्या पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

37. इसलिए प्राधिकारी ने पहले इसकी जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण निरंतर आर्थिक क्षति हुई है। उसके बाद इसकी जांच की गई है कि संबद्ध देशों से शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध - 2 के अंतर्गत निर्धारित विधि के अनुसार घरेलू उद्योग को होने वाली आर्थिक क्षति की जांच की गई है।

ज. 2 घरेलू उद्योग का वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज. 2.1 घरेलू उद्योग के निवेदन

38. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा पाटन-रोधी शुल्क के कारण कम है। यदि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो इन देशों के लिए बाढ़ का द्वारा जाएगा और घरेलू उद्योग को एक बार फिर से अत्यधिक क्षति होने लगेगी। इससे (क) समीक्षा से पहले विण्णतनाम से आयातों के पैटर्न में अंतरण और पाटन-रोधी शुल्क के संशोधन, (ख) उत्पाद के अत्यधिक पाटन, (ग) उत्पाद के संबंध में अत्यधिक कीमत में कटौती, (घ) संबद्ध उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता और (घ) संबद्ध देशों से इस समय अत्यधिक निर्यात का होना स्पष्ट सिद्ध होता है।
- (2) थाईलैंड और विण्णतनाम से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है, हालांकि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क के फलस्वरूप पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो इन देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटन बढ़ जाएगा।
- (3) घरेलू उद्योग को वर्तमान स्रोतों से पाटन होने और साथ ही मांग में कुछ गिरावट आने दोनों के कारण नुकसान हो रहा है। जबकि यह माना जाता है कि उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट आने के लिए मांग में गिरावट आंशिक रूप से उत्तरदायी है, फिर भी इन देशों से पाटन की उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को घोर क्षति पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त मुख्यतया जिस कीमत पर घरेलू उद्योग को बाजार में विचाराधीन उत्पाद को बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कारण देश में विचाराधीन उत्पाद का पाटन होना है।

- (4) पाटन-रोधी शुल्क के बिना डीवीडी-आर के संबंध में कीमत में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है। इससे पता चलता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और मौजूदा शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में अत्यधिक सीमा तक कटौती करेंगे।
- (5) आयातित और घरेलू कीमतों के बीच के अंतर को देखते हुए पाटन-रोधी शुल्क की समाप्ति से फलस्वरूप बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अत्यधिक न्यूनीकरण होगा।
- (6) उत्पाद की विश्व में धीमी मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता कम कर दी है और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखा हुआ है। कुछ समय से घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग घरेलू और विश्व बाजार में उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को विनियमित कर रहा है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों से उत्पादन में इसी प्रवृत्ति का पता चला है और यह आधार वर्ष से कम हो गया है।
- (7) घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्रियों के संबंध में निरंतर वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर निरंतर नकारात्मक प्रतिलाभ हो रहा है, जिसमें जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है।
- (8) भारतीय बाजार में पाटित आयातों के प्रवेश किए जाने की संभावना से बाजार में सुस्थिर रहने के लिए घरेलू उद्योग के पास निम्नतर कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को लागतों में होने वाली वृद्धि के समानुपात अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका जाएगा। घरेलू उद्योग को बड़े हुए वित्तीय घाटों का नुकसान उठाना पड़ेगा।
- (9) घरेलू उत्पादकों के समग्र बाजार का हिस्सा उसी क्षेत्र में बना हुआ है। मौजूदा शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा बढ़ेगी और ये बाजार पर कब्जा कर लेंगे जिसके कारण घरेलू उद्योग को और क्षति होगी।
- (10) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की औसत माल सूची के स्तर में गिरावट आई है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि याचिकादाता ने माल सूची के स्तरों को नियंत्रित रखने के लिए अपने उत्पादन को विनियमित कर दिया है।

ज. 2.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

39. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बारे में कोई निवेदन नहीं किया है।

ज. 2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों के आलोक में प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति के संभावित मुद्दों की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जांच की है।

41. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11 में ऐसी व्यवस्था है कि “.....सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं.....”, क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया में उन कारकों की जांच करना शामिल होगा जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होती है। कीमतों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया जाना आवश्यक समझा गया है कि इसकी जांच की जाए कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा अत्यधिक सीमा तक कीमतों का न्यूनीकरण करते अथवा कीमतों में वृद्धि होने को रोकते जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो सकती थी।

42. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभ प्रदता, निबल बिक्री वृत्त, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर विचार किया है।

43. वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभ प्रदता पर उनके प्रभाव की जांच की है, ताकि क्षति के विद्यमान होने तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई है, की जांच की जा सके।

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस समय संबद्ध देशों के अतिरिक्त चीन, हांग कांग और ताईवान से संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है। प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने लिए अन्य स्रोतों के साथ-साथ इन सभी देशों से आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव पर विचार किया है, जिसमें ऐसी संभावित अवस्थिति शामिल है, जो कि संबद्ध देशों के संबंध में पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों के पाटित

आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी मूल्यांकन किया गया है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव की जांच की गई है, ताकि वर्तमान पाटन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके, जो कि निम्नानुसार है :-

(क) पाटित आयातों के मात्रा के प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(1) संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

45. पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों की जांच करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह क्षति की जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात के आंकड़ों के व्यौरों की व्यवस्था करें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने चीन, हांग कांग और ताईवान के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के अपने अंतिम परिणाम में डीजीसीआईएंडएस के मार्च, 2014 तक के कारोबार-वार आयात के आंकड़ों की विस्तार से जांच की थी और उन पर विश्वास किया था। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ क्षति की जांच की अतिव्याप्त अवधि के लिए उन्हीं आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। वर्तमान जांच में सितंबर, 2014 तक की अवधि शामिल है। घरेलू उद्योग ने भी जांच अवधि (अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 तक) के लिए द्वितीयक स्रोत अर्थात् इंटरनेशनल ट्रेड एडवायजरी सर्विसिज (आईटीएस) से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और यह तर्क दिया है कि इन आंकड़ों में अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2014 की अवधि के दौरान जेएनपीटी और पटपडगंज आईसीडी के आयातों के कुछ कारोबार शामिल हैं, जो कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। इसलिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में निर्दिष्ट कारोबार के साथ-साथ इन अतिरिक्त कारोबार पर विचार किया गया है, जैसा कि इस जांच के प्रयोजनार्थ ऊपर उल्लेख किया गया है। इस जांच के लिए विचारित आंकड़ों को एक सार्वजनिक फोल्डर में रखा गया है। तदनुसार जांच विश्लेषण अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात निम्नानुसार हैं :-

मात्रा लाख अदद में

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि | जांच अवधि पश्चात |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| आयातों की मात्रा | | | | | | |
| संबद्ध देश | 283.37 | 271.99 | 121.50 | 74.51 | 49.67 | - |
| थाईलैंड | 78.44 | 13.60 | - | 52.50 | 35.00 | - |
| विएतनाम | 204.93 | 258.39 | 121.50 | 22.01 | 14.67 | - |
| जिन देशों पर शुल्क लग रहा है | 21.77 | 2.04 | 1.66 | 11.25 | 7.50 | 55.93 |
| चीन जनवादी गणराज्य | 20.27 | 2.04 | 1.56 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| ताईवान | 1.49 | - | 0.10 | 10.50 | 7.00 | 54.93 |
| हांग कांग | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देश | 338.03 | 295.85 | 174.08 | 211.03 | 140.68 | 54.00 |
| कुल आयात | 643.16 | 569.88 | 297.24 | 296.79 | 197.86 | 109.93 |

46. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि आधार वर्षों की तुलना में कुल आयातों में लगभग 70% की गिरावट आई है और क्षति जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा में भी गिरावट आई है और यह जांच अवधि में कम है। जांच अवधि (अक्टूबर, 2014 - मार्च, 2015) में संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि जांच अवधि पश्चात ताईवान से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। याचिकादाता ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा में विएतनाम पर शुल्क बढ़ाने और निर्णायक समीक्षा जांच में ताईवान के खिलाफ कम शुल्क करने से रिटेक जिसकी विएतनाम और ताईवान दोनों में उत्पादन क्षमताएं स्थापित हैं, ने ताईवान से अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के निर्यात करने शुरू कर दिए थे। इसलिए विएतनाम से पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में विएतनाम से पुनः निर्यात होने शुरू होने लगेंगे।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है और उपरोक्त आयात आंकड़ों से पता चलता है कि ताईवान को छोड़ कर उन देशों से आयातों ने भी स्थिर गिरावट दर्शाई है, जिनमें निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों में कटौती के बाद प्रवृत्ति उलट गई थी।

(2) मांग और बाजार का हिस्सा

48. भारत में संबद्ध वस्तुओं में घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों की मांग और बाजार के हिस्से का मूल्यांकन, घरेलू उद्योग की बिक्रियों और आयातों को ध्यान में रख कर किया गया है।

मात्रा लाख अदद में

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि | जांच अवधि पश्चात |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|------------------|
| घरेलू उद्योगकी बिक्रियां | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 99 | 82 | 72 | 72 | 46 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 198 | 163 | 144 | 144 | 92 |
| संबद्ध देश | 283 | 272 | 122 | 75 | 50 | 0 |
| जिन देशों पर शुल्क लग रहा है | 22 | 2 | 2 | 11 | 8 | 56 |
| अन्य देश | 338 | 296 | 174 | 211 | 141 | 54 |
| प्रवृत्ति | 100 | 88 | 51 | 42 | 42 | 32 |
| कुल मांग | 6,681 | 6,965 | 5,563 | 7,252 | 4,835 | 1,601 |

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी समान प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि इसी अवधि के दौरान अन्य घरेलू उत्पादकों ने घरेलू बाजार में फायदा उठाया है और उनकी बिक्रियों में लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में कुल आयातों में 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। आयातों में ऐसी गिरावट प्रत्यक्षतः अनेक देशों के खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के कारण आई है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि आयातों द्वारा खाली किए गए आंशिक भाग को अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा अधिग्रहीत किया जा रहा है, हालांकि उनकी बिक्रियों की मात्रा, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा की तुलना में बहुत कम है।

50. मांग में सामान्य प्रवृत्ति की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में विभिन्न व्यापारियों के बाजार के हिस्से की प्रवृत्तिकी जांच की है, जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि | जांच अवधि पश्चात |
|---|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|------------------|
| घरेलू उद्योगकी बिक्रियां | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 190 | 196 | 198 | 198 | 193 |
| संबद्ध देश | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 92 | 51 | 24 | 24 | 0 |
| थाईलैंड | % | 1.17 | 0.20 | - | 0.29 | 0.29 | - |
| विएतनाम | % | 3.07 | 3.71 | 2.18 | 0.31 | 0.31 | - |
| जिन देशों पर पहले से ही शुल्क लग रहा है | % | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.66 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| चीन जनवादी गणराज्य | % | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - |
| ताईवान | % | 0.02 | - | 0.00 | - | - | 1.66 |
| हांग कांग | % | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देश | % | 5.06 | 4.25 | 3.13 | 2.64 | 2.64 | 2.13 |

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि संबद्ध देशों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है, क्षति की जांच अवधि में डीवीडी-आर के लिए घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा लगभग वही बना हुआ है। अन्य देशों तथा पाटन-रोधी शुल्क देने वाले देशों द्वारा खाली किए गए बाजार के हिस्सों को अन्य भारतीय उत्पादकों ने अधिग्रहीत कर लिया है। क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से डीवीडी-आर के आयात की मात्रा और उसका बाजार का हिस्सा नगण्य है।

52. इसलिए घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का अत्यधिक मात्रा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि संबद्ध देशों से संचयी आयात बहुत तुच्छ मात्रा हैं और घरेलू मांग में अत्यधिक गिरावट आई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके लिए निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते क्षति की जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा प्रासंगिक नहीं है और यह शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों की संभावित स्थिति तथा घरेलू उद्योग की दशा की सही छवि प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

(ख) पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

53. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत में ह्रास होने और कीमत के न्यूनीकरण के प्रसंग में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उत्पान की लागत, निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) और घरेलू उद्योग को क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

54. घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग को करें, छूटों, डिस्काउंट्स और कमीशन पर हुए व्यय को समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत तय की है और उसकी तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री होना तय किया जा सके। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उपयुक्त रूप से विचार करके घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन, उसकी सुसंगत पद्धति के अनुसार किया गया है। इसकी स्थिति निम्नानुसार है :-

(1) कीमत में कटौती

55. चूंकि पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है, इसलिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत कटौती के प्रभाव का विश्लेषण, घरेलू बिक्री कीमतों की तुलना पाटन-रोधी शुल्कों के बिना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ करके और किया गया है, ताकि उसके प्रभाव को, यदि कोई है, देखा जा सके। इस प्रकार से तय की गई कीमत में कटौती निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि |
|---|----------|---------|---------|---------|-----------|
| पाटन-रोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती | | | | | |
| संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य | रुपए/अदद | 3.73 | 3.46 | 3.94 | 4.40 |
| प्रवृत्ति | | 100 | 93 | 106 | 118 |
| निबल बिक्री कीमत | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 112 | 116 | 111 |
| कीमत कटौती | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 150 | 136 | 98 |
| कीमत कटौती (%) | % | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | % सीमा | 30-40 | 40-50 | 35-45 | 25-35 |
| पाटन-रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती | | | | | |
| संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य | रुपए/अदद | 5.05 | 4.88 | 5.57 | 6.04 |

| | | | | | |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| प्रवृत्ति | | 100 | 97 | 110 | 120 |
| निबल बिक्री कीमत | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 112 | 116 | 111 |
| कीमत कटौती | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से डीवीडी-आर के पाटित आयातों का पहुंच मूल्य, याचिकादाता घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से अत्यधिक कम है। जहां तक कि समग्र क्षति अवधि के दौरान शुल्क अदा किए गए पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं, हालांकि आयातों की मात्रा निरंतर कम है।

(2) पाटित आयातों के कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के प्रभाव

57. घरेलू कीमतों पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली की प्रवृत्ति की तुलना, पाटन-रोधी शुल्क सहित और रहित संबद्ध देशों की बिक्रियों की लागत और आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, ताकि इसकी जांच की जा सके कि क्या कीमतों में अत्यधिक सीमा तक ह्रास अथवा न्यूनीकरण हो रहा है।

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| घरेलू बिक्रियों की लागत | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 109 | 136 | 145 |
| घरेलू बिक्री कीमत | रुपए/अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 112 | 116 | 111 |
| पाटन-रोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत | रुपए/अदद | 3.73 | 3.46 | 3.94 | 4.40 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 106 | 118 |
| पाटन-रोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत | रुपए/अदद | 5.05 | 4.88 | 5.57 | 6.04 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 110 | 120 |

58. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जबकि वर्ष 2012-13 से कम क्षमता उपयोग के कारण और अन्य कारकों से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है, फिर भी उनकी घरेलू बिक्रियों की कीमतें कम बनी हुई हैं और ये उत्पादन की लागत से बहुत कम हैं। इस अवधि के दौरान आयात की कीमतों में सामान्यतया लगभग 18-20% की वृद्धि हुई है। चूंकि लागत में वृद्धि, आंशिक रूप से कम क्षमता उपयोग होने और मूल्यह्रास आदि जैसे कारकों के कारण हुई है, इन कारकों के कारण लागत में वृद्धि पृथक् हुई है तथा आंकड़ों की जांच यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों के कारण कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ है। जांच अवधि में बिक्री कीमत को सामान्य लागत से कम पाया गया है, जिससे पता चलता है कि कीमतों में ह्रास मांग में गिरावट होने और पाटित आयातों के विद्यमान होने जैसे विभिन्न कारकों के कारण हुआ है।

(3) पाटित आयातों के कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव

59. पाटित आयातों के कम कीमत पर बिक्री होने, यदि कोई है, के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए उत्पाद की क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | थाईलैंड | विएतनाम | थाईलैंड | विएतनाम |
|-----------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | पाटन-रोधी शुल्क रहित | | पाटन-रोधी शुल्क सहित | |
| क्षति रहित कीमत | यूएस\$/000'अदद | *** | *** | *** | *** |
| पहुंच कीमत | यूएस \$/000' अदद | 71.61 | 73.96 | 97.59 | 103.72 |
| क्षति मार्जिन | यूएस \$/000' अदद | *** | *** | *** | *** |
| क्षति मार्जिन | % | *** | *** | *** | *** |
| क्षति मार्जिन | % सीमा | 55-65 | 50-60 | 15-25 | 10-20 |

60. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से डीवीडी-आर के आयातों का पहुंच मूल्य, ऐसे आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की डीवीडी-आर की क्षति रहित कीमत से कम रहा है, जिससे कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव का पता चलता है। शुल्क लगाने के बाद भी कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन अत्यधिक है।

ज. 3 घरेलू उद्योग की अन्य आर्थिक प्राचलों की जांच

61. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में ऐसी अपेक्षा है कि क्षति की निर्धारण करने की प्रक्रिया में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की सार्थक जांच करना निहित है। नियमावली में आगे यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का सार्थक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना निहित होना चाहिए जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल हैं।

62. घरेलू उद्योग से संबंधित उपरोक्त विभिन्न क्षति प्राचलों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

63. नीचे तालिका से क्षति की जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों का पता चलता है।

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|
| क्षमता | लाख अदद | 18,921 | 18,889 | 18,892 | 26,492 | 17,662 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 |
| उत्पादन | लाख अदद | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 75 | 57 | 57 |
| क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 75 | 61 | 61 |
| घरेलू बिक्रियों की मात्रा | लाख अदद | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 99 | 82 | 72 | 72 |

64. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में अपनी क्षमताओं को न्यूनतम रूप से सुव्यवस्थित बना लिया है। तथापि, जांच अवधि में उसके उत्पादन में लगभग 43% तक की अत्यधिक कमी हुई है, जिससे उसका क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है, जो कि आधार वर्ष में 75% से अधिक स्तर से गिर कर जांच अवधि में 50% से नीचे गिर गया है। उत्पादन में ऐसी गिरावट

आने का कारण घरेलू विक्रियों में गिरावट होना भी है, जिसमें आधार वर्ष से लगभग 28% तक की गिरावट आई है और साथ ही निर्यात विक्रियों में गिरावट होना है, जो की जांच अवधि के दौरान अत्यधिक कम हुई हैं, जिसका प्रत्यक्ष कारण उत्पाद की विश्व मांग में गिरावट आना है।

(ख) लाभ/हानि, नकदी प्रवाह,नियोजित पूंजी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

65. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन की उपरोक्त प्राचलों के रूप में जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | वार्षिकीकृत जांच अवधि |
|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| निबल लाभ/(हानि) | लाख रूपए | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -85 | -205 | -248 |
| निबल लाभ/(हानि) | रूपए प्रति अदद | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -86 | -251 | -346 |
| निबल लाभ | लाख रूपए | *** | *** | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 143 | -54 | -324 |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ | % | (***) | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | -84 | -346 | -761 |

66. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि हालांकि याचिकादाता घरेलू उद्योग वर्ष 2011-12 तक संबद्ध वस्तुओं की अपनी घरेलू विक्रियों में नकदी लाभ अर्जित कर रहा था, लेकिन उसके बाद घरेलू बाजार में कीमतों में समनुरूप वृद्धि किए बिना लागत में हुई अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उसकी घरेलू विक्रियों पर नकदी लाभ अत्यधिक रूप से नकारात्मक बन गया है। समस्त क्षति अवधि के दौरान निबल लाभ नकारात्मक बना रहा और वर्ष 2012-13 से उसके घाटों में वृद्धि होने लगी है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, इस अवधि में लागत में वृद्धि होने का कारण मांग में गिरावट आने के कारण उत्पादन में गिरावट आना और अन्य कारक हैं तथा घरेलू उद्योग संबद्ध देशों सहित अन्य स्रोतों से पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण, हालांकि उनकी मात्रा कम है, कीमत में वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो पाया है। समग्र क्षति जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नकारात्मक बना रहा है और यह जांच अवधि के दौरान और भी बदतर हो गया है।

(ग) लाभ/हानि, नकदी प्रवाह, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

67. घरेलू उद्योग के अन्य वास्तविक प्राचलो की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | वार्षिकीकृत जांच अवधि |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|
| माल सूची | लाख अदद | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 77 | 62 | 51 |
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | 1,692 | 1,950 | 1,986 | 993 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 115 | 117 | 59 |
| प्रति व्यक्ति उत्पादकता | लाख अदद | 8.78 | 7.09 | 5.57 | 3.74 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 81 | 63 | 43 |
| वेतन | लाख रूपए | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 118 | 123 | 49 |

68. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की निर्मित माल सूची में गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है, क्योंकि याचिकादाता ने माल सूची के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए उत्पादन विनियमित किया है। तथापि, क्षमता और उत्पादन में कटौती होने के कारण रोजगार में कमी और सुव्यवस्थीकरण करने के बावजूद उत्पादकता में गिरावट आई है, क्योंकि क्षमता उपयोग घट कर 50% से कम हो गया है।

झ. कारणात्मक संबंध

69. नियमावली में प्राधिकारी को पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने का अधिदेश प्राप्त है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा इस संबंध में कोई भी तर्क नहीं दिए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में निम्नलिखित मुद्दे लाए गए हैं और गैर-आरोपण का विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार उनकी जांच की गई है।

(1) अन्य देशों से आयात

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि संबद्ध वस्तुओं के आयात संबद्ध देशों के अतिरिक्त अनेक अन्य देशों से हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ देशों के आयात नगण्य हैं अथवा उन पर शुल्क लग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात से अत्यधिक आयात हो रहे हैं। लेकिन ये आयात अधिक कीमतों पर होते हैं। तथापि, क्षति की जांच अवधि के दौरान अन्य स्रोतों से देश को होने वाले कुल आयातों में अत्यधिक गिरावट आई है। इसलिए अन्य स्रोतों से आयात घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।

(2) मांग में संकुचन

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार के साथ-साथ विश्व बाजार में उत्पादों की मांग में निरंतर गिरावट आई है। इस तथ्य को मानते हुए कि विश्व की मांग में गिरावट आने से जो कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री को प्रभावित करती है, प्राधिकारी ने दिनांक अक्टूबर, 2014 के अपने विगत परिणाम में यह नोट किया था कि हालांकि विगत कुछ वर्षों में भारत में डीवीडी की मांग में गिरावट आई है, जो कि विश्व की प्रवृत्तियों के अनुकूल है, फिर भी डीवीडी आगामी कुछ समय तक डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए एक मुख्य माध्यम बना रहेगा और इसलिए इसे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता है।

72. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि –

- हालांकि यूएसबी/पेन ड्राइव जैसे प्रतिस्पर्द्धी और नई प्रौद्योगिकी के उत्पादों तथा ब्लू रेज जैसे अन्य डाटा स्टोरेज के उपकरणों और मनोरंजन से संबंधित आवश्यकताओं के लिए अन्य इंटरनेट के मंचों की उपलब्धता के कारण विश्व बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है, फिर भी स्टोरेज मीडिया के एक उपकरण के रूप में डीवीडी-आर की अत्यधिक उपयोगिता है और इनका उपयोग कम से कम आगामी दस वर्षों तक निरंतर होता रहेगा। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन विभिन्न मीडिया के माध्यम से स्टोरेज और ट्रांसमिशन की प्रति जीबी लागत, डीवीडी-आर के उपयोग को और व्यावहारिक बनाए रखेगी और यह आगामी कुछ समय तक आकर्षिक विकल्प बनी रहेगी तथा वस्तुतः इन उत्पादों का उपयोग कुछ क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से किया जा रहा है और फोटो स्टेज, चिकित्सकीय निदानों जैसे नए क्षेत्र सामने उभर कर आ रहे हैं तथा चलचित्रों और खेलों आदि में इनकी मांग निरंतर बनी रहेगी। घरेलू उद्योग ने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक लागत विश्लेषण और विभिन्न स्टोरेज और ट्रांसमिशन विकल्पों के उपयोग का उल्लेख किया है जो कि निम्नानुसार हैं :-

| उत्पाद | बाजार कीमत रूपए/अदद | प्रति जीबी लागत रूपए/अदद | उपयोग | टिप्पणियां |
|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| सीडीआर | 8.5 | 12 | एक बार स्टोरेज | इसे अधिकतर डीवीडीआर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह डीवीडीआर से सस्ती है, इसलिए इनका अभी भी कुछ प्रयोग हो रहा है। |
| सीडीआर डब्ल्यू | 15 | 21 | बहुताधिक बार स्टोरेज | इसे अधिकतर डीवीडीआर डब्ल्यू द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह डीवीडीआर डब्ल्यू से सस्ती है, |

| उत्पाद | बाजार कीमत रूपए/अदद | प्रति जीवी लागत रूपए/अदद | उपयोग | टिप्पणियां |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | इसलिए इनका अभी भी कुछ प्रयोग हो रहा है। |
| डीवीडी- आर | 15 | 3 | एक बार स्टोरेज | इनमें निरंतर अत्यधिक गिरावट आ रही है। इसकी मांग निरंतर किराए की फिल्मों और खेलों के लिए है। फोटो के क्षेत्र में और चिकित्सीय निदान में इनकी मांग में वृद्धि हुई है। डीवीडी प्लेयरों की बिक्री से पता चलता है कि डीवीडी - आर की मांग में मौजूदा और संभावित वृद्धि → हुई है। |
| डीवीडी- आर डब्ल्यू | 40 | 10 | बहुताधिक बार स्टोरेज | इसे आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। डीवीडी-आर की तुलना में एक बार स्टोरेज करने तथा लाने-ले जाने के लिए अधिक महंगी है। डीवीडी-आर की तुलना में एक बार स्टोरेज करने तथा लाने-ले जाने के लिए कम महंगी है। |
| ब्लू रे | 150 | 6 | बहुताधिक बार स्टोरेज | इसे आसानी से लाया-ले जाया जा सकता है। एक बार स्टोरेज करने और ट्रांसमिशन के लिए महंगी है। |
| पेन ड्राईव | 200 | 25 | बहुताधिक बार स्टोरेज | इसे आसानी से लाया-ले जाया जा सकता है। एक बार स्टोरेज करने और ट्रांसमिशन के लिए महंगी है। इसकी अत्यधिक मांग नहीं बढ़ रही है। |
| क्लाउड सहित इंटरनेट | | 74 | डाउनलोडिंग, देखना, संप्रेषण और स्टोरेज | भारत में इंटरनेट का कम उपयोग (17%) हो रहा है। क्लाउड का उपयोग 5% से भी कम है। जनता को उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर और जानकारी की आवश्यकता होती है। इसकी परिवहनीयता कम है। यह महंगा है। |

- विकसित देशों में डीवीडी की मांग अभी भी अत्यधिक है, जहां इंटरनेट का उपयोग करने की व्यापक सुविधा उपलब्ध है। इसलिए यह निवेदन किया गया था कि आगामी वर्षों में भारत में डीवीडी की अत्यधिक मांग बनी रहेगी। इंटरनेट के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में इंटरनेट का 17% उपयोग किया जा रहा है, जो कि वर्तमान स्थिति में नगण्य है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इंटरनेट डीवीडी-आर के लिए मौत का कुंआ साबित होगा। डीवीडी जैसा वास्तविक मीडिया, अभी भी अनेक सेवाओं की तुलना में अत्यधिक चलचित्र राजस्व सृजित कर रहा है। उपहारों और क्रीडाओं के लिए संग्रहकों की आविष्ट आवश्यकताओं जैसे अनेक कारणों से वास्तविक मीडिया की मांग अभी भी अत्यधिक बनी रहेगी। भारत में केवल 9% जनसंख्या के पास कंप्यूटर अथवा लैपटोप हैं तथा केवल 3 % भारतीय जनसंख्या के पास इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर/लैपटोप हैं। इसलिए जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, पेन ड्राईव अथवा हैंड डिस्क का उपयोग करना या इंटरनेट से डाउनलोडिंग करना केवल इतनी जनसंख्या तक ही सीमित है। डीवीडी भी वहां अधिक प्रचलन में है, जहां बड़ा डाटा किफायती

कीमत पर बड़ी संख्या में लोगों में संवितरित किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेन ड्राईव जिसकी लागत 200 रूपए अथवा उससे अधिक होती है, की अपेक्षा डीवीडी की लागत 15 – 20 रूपए लागत प्रभावी है।

- यूएसबी/पेन ड्राईव का उपयोग केवल उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जहां उपभोक्ता को विषय वस्तु को अनेक बार लिखना पड़ता है। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए जहां उपभोक्ताओं को केवल एक बार लिखना होता है, डीवीडी-आर के बजाए यूएसबी/पेन ड्राईव का उपयोग, उसका अत्यधिक कम उपयोग करना होता है। डीवीडी-आर अधिक लागत प्रभावी है, क्योंकि (अंत प्रयोक्ता तक) उसकी लागत केवल 15 रूपए है, जबकि इसकी तुलना में पेन ड्राईव की सामान्य लागत 200 रूपए से अधिक होती है। यह निवदेन किया गया है कि पेन ड्राईव का उपयोग मुख्यतया डाटा/विषय वस्तु को बार-बार/बहुत बार स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसलिए स्टोरेज के माध्यम के रूप में बाजार में यूएसबी/पेन ड्राईव, डीवीडी-आर का एवजी नहीं हो सकता है।
- डीवीडी-आर सॉफ्टवेयर, मनोरंजन सामग्री आदि के संग्रहण के प्रयोजनार्थ एक उत्तम डाटा भंडारण का तंत्र है, जिसके लिए बहुत बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस उपयोगी क्षेत्रों में डीवीडी-आर के लिए मांग में तेजी से गिरावट आने के फलस्वरूप कंप्यूटर और इंटरनेट का गहन उपयोग नगण्य है। चिकित्सकीय नैदानिक, फोटो-स्टोरेज आदि जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों से डीवीडी के लिए नई मांग का सृजन होगा।
- क्लाउड स्टोरेज के संबंध में जिसका उपयोग 5 % पर कम है, प्रति जीबी की लागत 74 रूपए होने का अनुमान है और इसलिए यह विकल्प अत्यधिक महंगा है, बिल्कुल भी लागत प्रभावी नहीं है और विलासिता है। इसलिए इसका उपयोग केवल उन उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि लागत के प्रति जागरूक नहीं हैं। तथापि, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, यह असंभव है कि डीवीडी-आर के लिए इस प्रकार की मांग को क्लाउड स्टोरेज जैसे सैद्धांतिक रूप से संभावित विकल्पों द्वारा छीन लिया जाएगा। इसका अभिप्राय ऐसे अनुप्रयोगों के लिए लगभग 4000 करोड़ रूप की लागत खर्च करना है, जो कि 170 करोड़ रूपए की लागत खर्च करके डीवीडी-आर द्वारा किए जा सकते हैं।
- अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें डीवीडी-आर की मांग है, मनोरंजन क्षेत्र है जिसमें किराए पर चलचित्र, खेल आदि शामिल हैं, जिनमें ब्लू रे और पेन ड्राईव की अत्यधिक क्षमता होने के बावजूद उनका तीव्रता से उपयोग नहीं किया जाता है। उभरते क्षेत्रों में फोटोग्राफी सहित चिकित्सा और अस्पताल के क्षेत्र शामिल हैं।
- उपरोक्त से ऐसा पता चलता है कि हालांकि विगत कुछ वर्षों से भारत में डीवीडी की मांग में गिरावट आई है, जो कि वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, फिर भी आगामी कुछ समय तक डीवीडी डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए निरंतर मुख्य माध्यम बना रहेगा।

73. गैर-आरोपित कारण के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे की जांच यह देखने के लिए की गई है कि क्या देश में मांग और समग्र वैश्विक मांग में गिरावट आने का कारण अन्य प्रौद्योगिकियों का उभरना है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने के कारण निम्नानुसार है :-

- विभिन्न स्रोतों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार स्टोरेज उपकरणों की मांग – पूर्ति की स्थिति के विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि विश्व का रिकार्डेबल/रि-रिकार्डेबल डिस्क का उत्पादन वर्ष 2012 में 12.3 बिलियन डिस्क था, जो कि वर्ष 2015 में घट कर 9.9 बिलियन डिस्क रह गया है और डीवीडी-आर का उत्पादन, जो कि वर्ष 2012 में 6.3 बिलियन डिस्क था, घट कर इस समय 5.1 बिलियन डिस्क रह गया है। तथापि, रिकार्डेबल/रि-रिकार्डेबल डिस्क के कुल उत्पादन में डीवीडी-आर का अंशदान 49% से बढ़ कर 51 % (फ्यूचरसोर्स कंसल्टिंग लिमिटेड) हो गया है। विश्व के रिकार्डेबल ऑप्टिकल डिस्क बाजार के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक यह 4.224 बिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि डाटा की सिक्युरिटी और स्टोरेज के बारे में जागरूकता बढ़ने से इन उत्पादों की मांग बढ़ने की आशा है।
- सीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि भारत में ऑप्टिकल डिस्क बाजार में लगभग 9.6% सीएजीआर (2012-16) का संकुचन हुआ है, डीवीडी-आर बाजार अभी भी मजबूती से चल रहा है, जिसमें अधिकतम गिरावट सीडी-आर के क्षेत्र में आई है। रिपोर्ट से ऐसा भी पता चलता है कि फोटो क्षेत्र और अस्पताल के नैदानिक क्षेत्र में इनकी खपत में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में भारत में डीवीडी प्लेयरों का अत्यधिक मात्रा में प्रवेश होने से ऐसा स्पष्ट होता है कि इस उत्पाद की अभी भी अत्यधिक मांग है, जो कि कम से कम अगले 5 से 10 वर्षों तक निरंतर बनी रहेगी।

74. उपरोक्त जांच से ऐसा पता चलता है कि हालांकि स्टोरेज मीडिया उपकरण के रूप में डीवीडी-आर की मांग में गिरावट आ रही है, फिर भी उत्पाद की अभी भी पर्याप्त मांग है और उत्पाद आगामी कुछ समय तक विश्व में अपनी निरंतर विशेष उपस्थिति बनाए रखेगा। ऐसी गिरावट से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि याचिकादाता उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक घरेलू और निर्यात बिक्रियां होती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या घरेलू उद्योग की निष्पादन में वर्तमान गिरावट आने के लिए केवल मांग में गिरावट आने को ही पूर्णतया जिम्मेदार माना जा सकता है।

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की अत्यधिक उच्च क्षमताएं विद्यमान हैं और उसका घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजार में मुख्य अंशदान था। इन क्षमताओं का सृजन उस समय किया गया था जब इन उत्पादों की मांग बहुत अधिक थी और उत्पाद के लिए अच्छा घरेलू और विश्व बाजार होने की संभावना थी। इस समय उत्पादन क्षमता के 50% से कम है और अब घरेलू मांग उसकी कुल क्षमता की लगभग 25% है, हालांकि इसकी निर्यात बिक्रियां ऐतिहासिक रूप से उसकी कुल बिक्रियों का लगभग 50 % तक थी। घरेलू और विश्व दोनों बाजारों में गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है, हालांकि पूर्णरूपेण घरेलू और विश्व बाजार में इसकी अभी भी अत्यधिक मांग है और यदि कीमतें सही हों तो याचिकादाता उनको पूरा कर सकता है।

76. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जब कि मांग में गिरावट आने से मुख्यतया याचिकादाता घरेलू उद्योग का वास्तविक कार्य-निष्पादन प्रभावित हुआ है, विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति ने स्थिति को और बदतर बना दिया है, क्योंकि इसने उसकी लागत की वसूली करने के लिए कीमत के सुव्यवस्थीकरण को रोक है। इसलिए केवल मांग की स्थिति को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(3) खपत का पेटर्न

77. जैसा कि पिछले भाग में उल्लेख किया गया है, अन्य प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों की तुलना में डीवीडी की खपत के पेटर्न से ऐसा पता चलता है कि भारत में अभी भी डीवीडी-आर की अच्छी खपत और मांग है और यह काफी समय तक निरंतर ऐसी ही बनी रहेगी। इसलिए खपत के पेटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए पूर्णतया जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(4) प्रतिस्पर्द्धता की स्थितियां

78. याचिकादाता घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में प्रमुख खिलाड़ी है और अन्य उत्पादकों का बाजार में बहुत कम हिस्सा है। निवेश से ऐसा नहीं पता चला है कि प्रतिस्पर्द्धता की स्थितियां अथवा व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां घरेलू उद्योग की क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

(5) प्रोद्योगिकी में विकास

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश से ऐसा नहीं पता चला है कि उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया अथवा उपयोग की प्रोद्योगिकी में किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन हुआ है, सिवाए इसके कि नई प्रोद्योगिकी और पेन ड्राईव, ब्लू-रेज और इंटरनेट आधारित ट्रांसमिशन ने प्रवेश किया है, जिसका उल्लेख ऊपर पैरा (2) में किया गया है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति के कारण हो सकते हैं।

(6) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

80. क्षति की जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यातों की मात्रा में गिरावट आई है, जो कि विश्व की प्रवृत्ति के अनुरूप है तथा इससे उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आने के रूप में घरेलू उद्योग की क्षति बढ़ गई है।

| विवरण | यूनिट | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिकीकृत जांच अवधि |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|
| निर्यात | लाख अदद | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 103 | 62 | 132 | 67 |

81. तथापि, विगत भाग में क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर आधारित है, जो कि पाटित आयातों से प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात बाजारों में कीमतों और लाभप्रदता को पृथक किया गया है। इसलिए हालांकि निर्यात निष्पादन में गिरावट आने से क्षति हुई है, घरेलू उद्योग को उसके निर्यात निष्पादन के कारण क्षति हुई के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं हैं।

झ. वर्तमान क्षति और क्षति के संबंधों पर निष्कर्ष

82. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्राचलों और गैर-आरोपित कारकों की उपरोक्त जांच से ऐसा पता चलता है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग को, उत्पादन और बिक्री में कमी होने, क्षमता उपयोग में गिरावट आने, घाटों में वृद्धि होने और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ के कारण क्षति हुई है। यह क्षति अत्यधिक है और आर्थिक है। तथापि, इस समय संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा इतनी कम है कि पाटित आयातों का विशेष प्रभाव प्रतीत नहीं होता है अथवा इस समय आर्थिक नहीं हो सकता है। संबद्ध देशों से आयातित डीवीडी-आर के पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं और साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री करने के प्रभाव भी डाल रहे हैं, हालांकि उनकी मात्रा कम है। दूसरी ओर मांग की स्थिति और क्षमताओं की जांच करने से ऐसा पता चलता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान ऐसी क्षति मुख्यतया उत्पाद की घरेलू और विश्व मांग में गिरावट आने से हुई है, हालांकि पाटित आयातों के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है, क्योंकि उसने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अपनी कीमतों को लाभप्रद के स्तर तक बढ़ाने से रोका है, जिससे कि उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री को नहीं बढ़ा सका है अपनी लागत को कम नहीं कर सका है। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि जब कि वर्तमान पाटित आयात इस समय घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमुख कारण नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपने कीमत प्रभाव के कारण उद्योग को अपने निष्पादन में सुधार करने और स्वस्थ होने में समर्थ नहीं बनने नहीं दिया है।

ञ. क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा आवृत्ति होने की संभावना

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का संकेन्द्रण इसकी जांच करने पर है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो कैसी स्थिति होने की संभावना होगी भले ही कोई वर्तमान क्षति नहीं हो और/अथवा कारणात्मक संबंध नहीं हो। विगत भाग में पाटन के निरंतर बने रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में यह सिद्ध हो गया है कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन के निरंतर बने रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह भी स्थापित हो गया है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है, हालांकि पाटित आयातों के कारण ही ऐसी क्षति नहीं हो रही है। इसलिए प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्षति निरंतर जारी रहेगी अथवा गहन होगी।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

84. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया गया है कि समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है, बल्कि यह भी देखना है कि क्या ऐसे शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति में पाटन निरंतर जारी रहेगा अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी और क्या घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी अथवा यदि ऐसे शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति की पुनरावृत्ति होगी। इस संबंध में याचिकादाता द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति में डीवीडी-आर के संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (ख) घरेलू उद्योग के निरंतर प्रतिकूल निष्पादन से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर उसके लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में और गिरावट आएगी। इस प्रकार वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में और गिरावट आने की संभावना है।
- (ग) भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति निरंतर अत्यधिक बनी हुई है। हालांकि इसकी वर्तमान मात्रा कम है, फिर भी पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर उनकी मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।
- (घ) देश में पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति घरेलू उद्योग को उचित कीमत प्राप्त करने से रोक रही है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
- (ङ) प्राचलों की संख्या के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक बन गई है। इन परिस्थितियों में पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर उसकी संवृद्धि और नकारात्मक हो जाएगी।
- (च) घरेलू उद्योग इस समय संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभावों का सामना कर रहा है। संबद्ध देशों से पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति न केवल निरंतर जारी रहेगी, बल्कि और भी बढ़ेगी होगी।

- (छ) यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो उससे स्पष्ट पता चलेगा कि विगत में विभिन्न देशों से पाटन करने की सुसंगत पद्धति अपनाई जा रही है। यदि एक सेट के देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो देशों के दूसरे सेट से पाटन शुरू हो जाता है। आयातों में ऐसे अंतरण से स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातक जानबूझ कर और ईमानदारी से पाटन कर रहे हैं, ताकि वे अपनी स्थापित अत्यधिक क्षमताओं के कारण विश्व बाजार में अपने बाजार के हिस्से को बनाए रख सकें।
- (ज) विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपने स्रोत का निर्णय मुख्यतया कीमत को ध्यान में रख कर करते हैं। यदि विभिन्न पाटित स्रोतों से संचयी रूप से कीमत में कटौती की जांच की जाती है, तो यह देखा जा सकता है कि पाटित आयातों द्वारा भारत औसत कीमत में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है। विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह स्वभाविक है कि संबद्ध देशों में उत्पादक ऐसी कीमतों से भिन्न कीमतें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिन कीमतों पर अन्य विदेशी उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य देशों से आयातों से होने वाली कीमत में कटौती, ऐसा स्पष्ट संकेतक है जिससे पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से कीमत में कटौती किए जाने की संभावना होगी।
- (झ) डीवीडी के लिए विश्व की मांग में गिरावट आने के कारण पाटन होने और उसके परिणामी प्रभाव पड़ने की सुदृढ़ संभावना है। चूंकि डीवीडी के लिए विश्व की मांग में गिरावट आई है, संबद्ध देशों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इन देशों में उत्पादकों को व्यापक भारतीय बाजार में प्रवेश प्राप्त करने में आसानी होगी और जबकि अन्य क्षेत्रों में मांग में संकुचन हो रहा है, भारतीय बाजार में डीवीडी के लिए संपूर्ण मांग के निरंतर अधिक बने रहने की संभावना है।
- (ण) याचिकादाता को पहले ही समस्त प्राचलों के बतौर आर्थिक क्षति हो रही है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता मुख्यतया कीमत को ध्यान में रख कर अपने स्रोत का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता के कारण सन्निकट रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (ट) यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क को जारी रखने के लिए सभी परिस्थितियां विद्यमान रहें। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें एक अथवा अधिक प्राचलों के पूरा होने पर भी शुल्क निरंतर बनाए रखे गए हैं।
- (ठ) निर्णायक समीक्षा जांच की जांच अवधि के दौरान सूचित आयातों की कम मात्रा होने पर भी पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखा जा सकता है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें विदेशी प्राधिकारियों ने प्रथम और परवर्ती निर्णायक समीक्षाओं में शुल्क को निरंतर जारी रखा है।
- (ड) भारत ने आयातों की कम मात्रा होने के बावजूद अनेक उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्कों को बढ़ाया है। इस संबंध में कुछेक उल्लेखनीय मामलों में जिंक ऑक्साईड, सोडियम हाईड्रोसलफाईड, डकट टाईल आयरन पाईप, फ्रंट एक्सिल बीम और स्टीयरिंग नुक्लस, फुली ड्रान यार्न, पोटेशियम परमान्गेनट आदि शामिल हैं।
- (ढ) इसलिए पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसलिए प्राधिकारी को लागू शुल्क को निरंतर जारी रखना चाहिए।

ब.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

85. इस संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

86. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क का समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग का होने वाली क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी आवृत्ति की जांच करने के लिए संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की वर्तमान मात्रा और मूल्य तथा घरेलू उद्योग की घरेलू विक्रियों की मात्रा पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य देशों से वर्तमान आयातों की मात्रा कम है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विभिन्न कारकों की उद्देश्य पूर्ण जांच करने के आधार पर पूर्व भाग में पाटन की जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना की संपुष्टि हो गई है। तदनुसार निम्नलिखित कारकों की जांच यह देखने के लिए की गई है कि क्या क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने कोई सन्निकट संभावना है।

(क) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

87. डीवीडी-आर के लिए मूल जांच और वर्तमान जांच दोनों में पाटन के मार्जिन का स्तर अत्यधिक है, हालांकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा कम है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य देशों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क इन देशों से बड़े पैमाने पर पाटित आयातों को रोकने में सफल रहे हैं, हालांकि इन देशों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएं विद्यमान हैं। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि हालांकि घरेलू उद्योग के पास समग्र मांग को पूरा करने की क्षमता है, फिर भी अनेक देशों से काफी कम कीमतों पर आयात हो रहे हैं। इसलिए इसकी अत्यधिक संभावना है कि यदि एक बार शुल्कों को हटा लिया जाता है, तो इन देशों से तुलनीय कीमतों पर आयात होने शुरू हो जायेंगे। इन कीमतों पर घरेलू उद्योग को सामान्य क्षति रहित कीमत को वसूल करने के लिए अपनी कीमतों में कटौती और कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ेगी। इसलिए घरेलू उद्योग को पाटन सहित अनेक कारकों के कारण निरंतर क्षति होती रहेगी और उसके बढ़ने की संभावना रहेगी।

(ख) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

88. भारत को संबद्ध देशों से जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए जा रहे हैं, वे पाटन के निरंतर रहने/बढ़ने की संभावना के संकेतक हैं। भारत में वर्तमान पहुंच कीमत, उत्पाद पर लागू पाटन-रोधी शुल्क को ध्यान में रखने के बाद भी सकारात्मक कीमत कटौती कर रही है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर भारतीय बाजार, संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए इतना आकर्षक हो जाएगा कि वे सीमान्त लागत कीमतों पर भारत में अपने निर्यात बढ़ा देंगे और ऐसी संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करने लगेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति बढ़ जाएगी।

(ग) विश्व मांग – आपूर्ति की स्थिति

89. विश्व के डीवीडी के बाजार में मांग और पूर्ति के बीच असमानता है। प्रतिस्पर्द्धी प्रोद्योगिकियों के सामने मांग की तुलना में उनके निर्माण की क्षमताएं अधिक हैं। इसलिए ऐसी स्पष्ट संभावना है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो विश्व के खिलाड़ी बाजार में प्रवेश पाने की आक्रामक कार्यनीतियां क्रियान्वित करेंगे और भारत में पाटन बढ़ा देंगे, जिसके फलस्वरूप कीमत में कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री होगी, जिससे घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग और लाभप्रदता पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।

90. याचिकादाता घरेलू उद्योग के पास घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं। जबकि मांग में आई गिरावट ने उत्पादन और बिक्रियों को अत्यधिक प्रभावित किया है और क्षति पहुंचाई है, उद्योग के पुनरुद्धार के लिए घरेलू बाजार के हिस्से और कीमत की विशेष भूमिका है। इसलिए यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसी संभावना है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में अपने अत्यधिक अंशदान को गंवाना पड़ेगा और उससे क्षति के बढ़ जाने की संभावना होगी।

हितबद्ध पक्षकारों के पक्ष:प्रकटीकरण अनुरोध

91. प्रकटीकरण विवरण घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के दूतावासों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए भेजे गए थे। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने मांग परिदृश्य और पतन और क्षति के जारी रहने की संभावना अथवा पतन के संबंध में अनिवार्यतः अपनी स्थिति दोहराई है और नियत अवधि में शुल्क लगाए जाने को जारी रखने और वर्णित डॉलर के लिए अनुरोध किया है।

ट. क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन

92. प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना, जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस तरीके से तय किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

| विवरण | यूनिट | थाईलैंड | विएतनाम |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| क्षति रहित कीमत | यूएस \$/000'अदद | *** | *** |

| | | | |
|---------------|------------------|-------|-------|
| पहुंच कीमत | यूएस \$/000' अदद | 71.61 | 73.96 |
| क्षति मार्जिन | यूएस \$/000' अदद | *** | *** |
| क्षति मार्जिन | % | *** | *** |
| क्षति मार्जिन | % सीमा | 55-65 | 50-60 |

घ. क्षति और संभावित क्षति पर निष्कर्ष

93. निष्कर्ष में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश कर रही हैं, जो कि घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रही हैं। उनका पहुंच मूल्य का परिकलन करने के लिए इस समय उन पर लगाये जा रहे पाटन-रोधी शुल्क को ध्यान में रखे जाने के बाद भी पाटित कीमतें कम हैं। इसके अतिरिक्त आयात की कीमतें, प्राधिकारी द्वारा सुसंगत पद्धति के अनुसार सभी असामान्य लागतों को हटाने के बाद भी याचिकादाता घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत अथवा उचित कीमत से काफी कम हैं। विश्व की मांग की स्थिति और विगत भाग में यथा- दर्ज किए गए अनुमानों तथा इन देशों के पास उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्पष्ट संभावना है कि पाटन निरंतर जारी रहेगा और उसमें और वृद्धि होगी, जब ये उत्पादक अपनी उत्पादन क्षमताओं को अनुकूलतम सीमान्त लागत कीमतों पर बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। यदि ऐसी प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है, तो जैसे ही शुल्क संरक्षण हटा लिया जाता है, यह घरेलू उद्योग की किसी भी कीमत की वसूली को रोकेंगा। यदि घरेलू बाजार की कीमतों की वसूली नहीं होती है, तो घरेलू उद्योग लागतों को कम करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने में सक्षम नहीं होगा तथा उसके घाटे और भी बढ़ेंगे।

94. घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक निवेश की लागत पर अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं। विगत स्थिति में यथा-विश्लेषित मांग की स्थिति से पता चलता है कि हालांकि यह उत्पाद गिरावट की स्थिति में अथवा समाप्ति के चरण में है, फिर भी कम से कम आगामी 5-10 वर्षों के लिए ऐसे पूर्णरूपेण उत्पाद की अत्यधिक मांग होगी, जिसे घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं में कुछ सुव्यवस्था करके पूरा कर सकता है। तथापि, यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो उत्पादन और बिक्री की मात्रा में और गिरावट आएगी और उससे उत्पादन पूर्णतया गैर-अर्थक्षम बन जाएगा, क्योंकि शुल्क के तत्व के बिना पाटित आयातों की वर्तमान कीमतें, घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागतों से कम होंगी और आयातों के और बढ़ने की संभावना होगी, क्योंकि उसका बाजार अभी भी विद्यमान है। इसलिए यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के निरंतर जारी रहने और क्षति के बढ़ने की स्पष्ट और सन्निकट संभावना है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

95. प्रयोक्ताओं और अन्य ऐसे हितबद्ध पक्षकारों के हितों के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जिनका सीधा उपयोग मनोरंजन और आई टी उद्योग तथा बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जाता है, जो कि शुल्कों के निरंतर जारी रहने से प्रभावित होगी। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में समान अवसरों वाली स्थिति सृजित करके खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटन-रोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरी ओर यदि पाटित आयातों के कारण हुई विकृति में सुधार नहीं किया जाता है, तो उससे उत्पादन का आधार समाप्त हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रयोक्ताओं के हितों पर अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ढ. सिफारिश

96. प्राधिकारी ने वर्तमान पाटन, क्षति तथा घरेलू उद्योग की हुई क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संबंध होने तथा शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति की जांच करने के लिए इस जांच की कार्यवाही शुरू की थी। उपरोक्त पैराओं में स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो गया है शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने स्पष्ट और सन्निकट संभावना है।

97. साथ ही यह भी सिद्ध हो गया है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी तथा यह और बढ़ेगी। इसलिए संबद्ध देशों से पाटन के निरंतर जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने/क्षति की पुनरावृत्ति के खिलाफ घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए शुल्कों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है।

98. मामले के वास्तविक सांचे में तथा डीवीडी-आर और डीवीडी-आरडब्ल्यू के वर्तमान पाटन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डीवीडी-आर पर शुल्कों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

99. इसलिए प्राधिकारी जांच अवधि के लिए परिकल्पित किए गए पाटन और क्षति मार्जिन के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क को, उसको लागू किए जाने की तारीख से आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं, ताकि पाटन की पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को उससे होने वाली परिणामी क्षति को रोका जा सके। प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डीवीडी-आर के लिए इस प्रकार से निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क निरंतर लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके।

100. विगत जांच में उद्भूत शुल्कों को निर्धारित शुल्कों के रूप में लगाया गया था। तदनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डीवीडी-आर के समस्त आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से नीचे तालिका के कॉलम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को आगे 5 वर्षों तक की अवधि के लिए निरंतर लगाए रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

| क्र.सं. | उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद | वस्तुओं का विवरण | वित्तिदेशन | उद्गम का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | शुल्क राशि | माप की इकाई | मुद्रा |
|---------|------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------|---------|----------|------------|---------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 8523 | डिजिटल वॉरेटॉइल डिस्क, रिकॉर्डेबल | डीवीडी-आर, डीवीडी+आर, एवं मिनिडीवीडी-आर | वियतनाम | कोई | कोई | कोई | 41.35 | प्रति 1000 नग | अम.डॉ. |
| 2 | -वही- | -वही- | -वही- | संबद्ध देशों को छोड़कर कोई देश तथा अन्य किसी अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क वाले देश | वियतनाम | कोई | कोई | 41.35 | -वही- | -वही- |
| 3 | -वही- | -वही- | -वही- | थाइलैंड | कोई | कोई | कोई | 43.70 | -वही- | -वही- |
| 4 | -वही- | -वही- | -वही- | संबद्ध देशों को छोड़कर कोई देश तथा अन्य किसी अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क वाले देश | थाइलैंड | कोई | कोई | 43.70 | -वही- | -वही- |

टिप्पणी

विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संबद्ध देशों के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अतिव्यापन है, उक्त संबद्ध देश के लिए लागू सीमा शुल्क, सीमा शुल्क अधिसूचना जिसमें कॉलम "मूल देश" के अंतर्गत उक्त देश विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है।

थ. आगे की प्रक्रिया

101. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील, संबद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

102. प्राधिकारी अधिनियम और नियमावली के संबद्ध प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई सार्वजनिक अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर यथा संस्तुत निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, संशोधन करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करने के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**New Delhi, the 15th March, 2016**FINAL FINDING**

Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of ‘Digital Versatile Discs-Recordable of all kinds (DVD-R)’ originating in or exported from Vietnam and Thailand.

F. No. 15/01/2015-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Act) read with Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred as the Rules).

A. Background of the Case

1. Whereas the Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, (hereinafter referred to as “the Authority”), *vide* Notification No. 14/16/2009-DGAD dated May/05/2009, initiated an anti-dumping investigation concerning import of ‘Digital Versatile Discs-Recordable of all kinds (DVD-R and RW), originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam. The Preliminary Findings were issued by the Authority, *vide* Notification No. 14/16/2009-DGAD dated Nov/13/2009 and the provisional anti-dumping duties were imposed by the Central Government, *vide* Notification No. 48/2010-Customs dated Apr/12/2010. The Final Findings were issued by the Authority, *vide* notification No. 14/16/2009-DGAD dated Jul/02/2010, recommending imposition of definitive duty.
2. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, *vide* Notification No.98/2010-Customs dated Sep/28/2010 on the imports of the above goods, originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam. The definitive duties were valid for a period of 5 years from the date of provisional duty i.e. till 11th April, 2015. Subsequently, on the request of the domestic industry the Authority initiated a Mid-term review investigation against imports of subject goods originating in or exported from Vietnam on Aug/16/2012 *vide* Notification No. 15/5/2012-DGAD and on the basis of the Final Finding of the Authority issued on Oct/15/2013, the duties were enhanced against the above goods originating in or exported from Vietnam, *vide* Customs Notification No. 34/ 2013-Customs (ADD) dated Dec/31/2013.
3. M/s Moser Baer India Limited, the major domestic manufacturer of the subject goods, filed a duly substantiated application before the Authority on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of duty and requested for a review of the same for continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R) only, originating in or exported from the above countries.
4. The domestic industry, in its petition for initiation of the sunset review, submitted that imports of DVD-RWs, which was also subjected to antidumping duties, were at significantly high prices and therefore, not affecting the domestic industry. It was also submitted that since DVD-RW production of the petitioner is extremely low compared to the production and sale of DVD-Rs, import of DVD-RWs no longer posed any threat to them in terms of dumping and injury. The Authority notes that in the sunset review investigation concerning China PR, Hong Kong and Chinese Taipei, after detailed examination the Authority excluded DVD-RW from the scope of imposition/extension of duty as this product was not found to be injuring the domestic industry and there was no likelihood of imminent

recurrence of injury on account of this product. Considering the above facts the Authority, in the initiation notification, excluded DVD-RWs from the scope of the current investigation also.

5. The duties were in force against Malaysia, Vietnam and Thailand. However, there was no import of the subject goods from Malaysia during last three years. The petitioner did not provide any credible *prima facie* evidence to establish likelihood of recurrence of dumping from Malaysia. Therefore, the Authority decided to restrict the review in respect of duty on Thailand and Vietnam only and Malaysia was dropped from the purview of the sunset review investigation.
6. Accordingly, on the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/01/2015-DGAD dated Mar/27/2015 to review the need for continued imposition of the duties in respect of 'Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R) only (herein after referred to as the subject goods), originating in or exported from Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
7. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Central Government up to and inclusive of 11th day of April, 2016, vide Notification No.12/2015-Customs (ADD) dated 11.04.2015.
8. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries only.

B. Procedure

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) and copies of the initiation notification and non-confidential petition were also made available to the embassies concerned with a request to make them available to all producers and exporters of the subject goods in their respective countries.
 - ii. The Authority forwarded copies of the public notice and copies of the non-confidential version of the petition to the following known producers/exporters in the subject countries and provided them opportunity to make their views known in writing within forty days thereof in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
 - a. M/s Jet-Thai Hi-Tech Co. Ltd. Thailand
 - b. M/s Ritek Vietnam Co. Ltd., Vietnam
 - iii. No response or submission has been filed by any of the producers/exporters from the subject countries. No submission has also been received from the Governments of the subject countries.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice and non-confidential petitions to the following known importers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Rashi Peripherals Pvt. Ltd.
 - b. Dynamic Overseas
 - c. Jas International
 - d. Hanix Overseas
 - e. Aditya Enterprises
 - f. Veeline Media Ltd.
 - g. Himalayan Times Pvt. Ltd.
 - h. Allied Electronics and Magnetics Ltd.

- i. Rana Peripherals Pvt. Ltd.
- v. No response or submission by way of response to the questionnaire has been submitted by any of the importers/users/other interested parties.
- vi. A copy of the initiation notification was also sent to the following other known domestic producers of the subject goods, namely, (i) Euro Multivision Ltd, (ii) Jupiter International Limited. No response has been received from these parties either.
- vii. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- viii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of import data of the subject goods for the injury period (2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013), including the POI (April 2013- March 2014).
- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- x. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India, as per its consistent practices, so as to ascertain if anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury, if any, to the domestic industry.
- xi. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on Feb/01/2016, which was attended only by the domestic industry and their representatives. The domestic industry was requested to file written submissions of their views expressed orally. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation and considered relevant by the Authority, have been taken on record addressed to the extent they are relevant and backed by evidence.
- xii. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer was carried out to the extent deemed necessary.
- xiii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used 'best information available' and has treated such parties as non-cooperative.
- xv. In this finding '***' represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xvi. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2013 to 31st September, 2014. The examination of trends in the context of injury analysis covers the periods April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013 and the POI.
- xvii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.60.81 = 1 US\$.

C. Scope of Product under consideration and like article

10. As noted in para-6 above the scope of the product under consideration for the current sunset review shall cover only all kinds of "Recordable Digital Versatile DVD-R, DVD+R, and mini DVD-R" (Hereinafter referred to as product under consideration or subject goods).
11. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submission in this regard. Therefore, the Authority confirms the scope of the product under consideration as above.

D. Domestic Industry and Standing

12. The petitioner has submitted that there are four other known producers of the product under consideration in the country – namely, Euro Multivision Limited, Jupiter International Limited and Next Star Digital. However, the petitioner, i.e. M/s Moser Baer India Ltd., commands more than 87% share in Indian production of the subject goods during the POI and therefore, constitute domestic industry and satisfy the standing requirement for the purpose of this investigation. None of the exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard or contested the claims of the domestic industry. Since there is no opposition from any interested party in the present investigation regarding the standing of the domestic industry and the production of the applicant producer constitutes major portion of the total production of the subject goods, the Authority has considered that the petitioner has the standing to file the application for sunset review and constitutes domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules.

E. Other submissions of the interested parties

13. The authority notes that no other interested party, except the petitioning domestic industry, has made any submission in response to the initiation of this sunset review. The submissions made by the domestic industry with regard to their claims of dumping, injury and causal links have been examined in the respective sections in this disclosure statement.

F. Determination of current Dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping**F.1 Legal Positions**

14. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

“The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

15. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:
- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
 - In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
 - Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
 - In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.
16. Therefore, the Authority first proceeded with the examination whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, before proceeding to injury examination and the likelihood of continuation or recurrence of injury.

F.2 Examination of Continuation of Dumping, if any: Methodology of determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin**F.2.1 Views of the Domestic Industry**

17. The petitioner domestic industry, in its petition, submitted that they made efforts to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Thailand and Vietnam. Efforts were also made to get evidence of price from published sources. However, they could not get any evidence of price in the domestic market of Thailand and Vietnam. In view of this, the petitioner constructed the normal values for all exporters/producers from Thailand and Vietnam based on their cost data on a conservative basis. The prices and consumption norms of the major raw

material, i.e., polycarbonate have been adopted on the basis of domestic industry's cost since the import prices reported by DGCI&S during the period were high.

F.2.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

18. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

F.2.3 Determination of Normal Value in Thailand and Vietnam

19. The sunset review was initiated on the basis of the above prima facie evidence of dumping as no direct and reliable evidence of prices of the subject goods in the subject countries was available to enable a fair comparison at that stage. However, The Authority provided adequate opportunity to the interested parties to provide appropriate information for determination of the normal values and export prices from the subject countries for a fair determination of current dumping as well as likelihood of continuation or recurrence of dumping as the case may be. Since none of the producers and exporters in Thailand and Vietnam has provided any information or evidence with regard to the Normal Value of the subject goods in those countries, the Authority is constrained to determine the normal value in these countries based on best facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry in terms of para-1 of Annex II to the Agreement on Anti-dumping.
20. Accordingly, Authority has constructed the normal value in Thailand and Vietnam on the basis of the cost of production of the petitioner domestic producer in India after making due adjustments for the international prices of major raw materials, and power cost as prevailing in the country, as the best information, with due provision for a reasonable profit. Accordingly, Normal Value of the subject good in Vietnam and Thailand have been determined as follows:

| | Vietnam | Thailand |
|--|----------------|-----------------|
| Particulars | Rs./pcs | Rs./pcs |
| Raw cost as per domestic price including packing material cost | *** | *** |
| Utilities | *** | *** |
| Conversion cost/SGA including interest | *** | *** |
| Profit | *** | *** |
| CNV (Rs./pcs) | *** | *** |
| CNV USD/ '000 pcs | *** | *** |
| Exchange Rate USD 1 = | 60.81 | 60.81 |

F.4 Export Prices

21. As none of the exporters of the subject countries has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the export prices for all exporters from subject countries on the basis of CIF price of imports to India as per the transaction-wise import data obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation in the country of export, clearing charges and Bank Charges as per best information available to arrive at the export prices at the ex-works level. Accordingly, export price from these countries work out as follows:

| Particulars | Unit | Thailand | Vietnam |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Volume of Imports | Lac Pcs | 52.50 | 22.01 |
| CIF Value of Imports | Rs.Lacs | 226.31 | 97.99 |
| CIF Price | Rs./Pc | 4.31 | 4.45 |
| Ocean Freight | Rs./Pc | 0.06 | 0.07 |
| Marine Insurance | Rs./Pc | 0.01 | 0.01 |
| FOB Export Price | Rs./Pc | 4.24 | 4.38 |
| Port Expenses @ 0.50 % | Rs./Pc | 0.02 | 0.02 |
| Inland Freight @ 0.50 % | Rs./Pc | 0.02 | 0.02 |
| Handling charges @ 1% | Rs./Pc | 0.04 | 0.04 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|
| Clearing charges @ 1% | Rs./Pc | 0.04 | 0.04 |
| Bank charges | Rs./Pc | 0.04 | 0.04 |
| Net Export Price | Rs./Pc | 4.07 | 4.20 |
| Exchange rate- US\$ | INR | 60.80 | 60.80 |
| Net Export Price | US\$/000Pcs | 66.96 | 69.16 |

F.5 Dumping Margins

22. The normal values so determined for the subject countries, as per the methodology indicated above, have been compared with the respective export prices at the ex-factory level so determined in the foregoing paragraphs, to arrive at the dumping margin for all the producers/exporters in the subject countries as follows:

| Particulars | Unit | Thailand | Vietnam |
|------------------|--------------|----------|---------|
| Normal Value | US\$/000'Pcs | *** | *** |
| Net Export Price | US\$/000'Pcs | 66.96 | 69.16 |
| Dumping Margin | US\$/000'Pcs | *** | *** |
| Dumping Margin | % | *** | *** |
| Dumping Margin | % Range | 70-80% | 60-70% |

23. The above assessment indicates that DVD-Rs continue to enter the Indian market, from Thailand and Vietnam, at dumped prices and the dumping margins are significantly high though the volume of imports are low during the POI. Therefore, the Authority has assessed the likelihood for continuation or recurrence of dumping of the subject goods as follows:

G. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

G.1 Views of the Domestic Industry

24. The petitioner domestic industry has submitted that there is a history of dumping of the subject goods from various countries, apart from the countries under investigation in this review, and the Authority has carried out several investigations against this product in the past resulting in imposition of antidumping duties as per the table given below:

| S. No. | Investigation | POI | Country | Dumping Margin % | ADD (USD/1000 pcs.) |
|--------|--|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1. | 1 st Investigation | April 2006 to June 2007 | China PR | 64.72 | 68.11-48.11 |
| | | | Hong Kong | 62.96 | 66.72 |
| | | | Chinese Taipei | 63.50 | 45.63 |
| 2. | 2 nd Investigation | April 2008 to March 2009 | Malaysia | 34.05 | 35.92 |
| | | | Thailand | 22.51 | 25.98 |
| | | | Vietnam | 64.09 | 29.75-50.51 |
| 3. | MTR of the 2 nd investigation | April 2011 to March 2012 | Vietnam | 105-115% | 73.01 |
| 4. | SSR of 1 st Investigation | April 2012- March 2013 | China PR | 100-120% | 36.67 |
| | | | Hong Kong | - | 36.67 |
| | | | Chinese Taipei | 25-35% | 22.39 |

25. Domestic Industry argues that all the investigations in the past concluded on DVDs have shown significant dumping of these products showing the fact of dumping by global producers. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the market share of the domestic industry.
26. It has been further argued by the domestic industry that Ritek is one of the known major producer and exporters of the product under consideration having production facilities in Taiwan, China and Vietnam. After imposition of anti dumping duty and with a view to circumvent anti-dumping duty on imports from Taiwan, Ritek set up some manufacturing facilities in Vietnam and started dumping from Vietnam. Ritek did not cooperate with the Designated Authority in the first investigation in respect of imports from Taiwan. However, when the Designated Authority subsequently initiated investigations in respect of Vietnam, Ritek responded and participated fully in the investigations and significantly low quantum of anti-dumping duty was imposed on Ritek in respect of imports from Vietnam. The company intensified dumping from Vietnam and continued to export from Vietnam. Imports from Taiwan and China remained very low in volumes during this period. The domestic industry filed petition for review in respect of imports from Vietnam in view of intensified dumping. The company did not respond to the midterm review. The Designated Authority, after conducting detailed investigation, recommended imposition of enhanced duty on imports from Vietnam at the rate of US\$73.01/1000 Pcs, which was subsequently imposed by Ministry of Finance.
27. When the sunset review was initiated against imports of the subject goods from Taiwan in November 2014 M/s. Ritek, who has plants both in Vietnam and Taiwan, did not participate in the said investigation. Given that Vietnam entity is a wholly own subsidiary of Taiwan entity, significant issues were raised by petitioner with regard to valuation of raw materials, interest costs and other costs. It was contended by the petitioner that the major raw materials for the Vietnam plant were being procured by M/s Ritek Taiwan. Further, it was argued that significant overhead costs were not being booked in the books of Vietnam and these were being recorded in Taiwan books.
28. The Authority concluded the sunset review investigation and the duty against the imports from Taiwan was significantly reduced to US\$22.39/1000 Pcs from US\$65.63/1000 Pcs. This has resulted in significant shift in exports from Vietnam to Taiwan as can be seen from the Post POI data of this investigation as given below:

| Imports from | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI | Post POI |
|--------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------|----------|
| Vietnam | Lac.Pcs | 204.93 | 258.39 | 121.50 | 22.01 | 14.67 | - |
| Taiwan | Lac.Pcs | 1.49 | - | 0.10 | 10.50 | 7.00 | 54.93 |

29. The domestic industry has argued that under these circumstances, in case the present anti-dumping duty is removed from Vietnam, the company will shift back dumping from Vietnam, as duties are in force against Taiwan. Further, it has been argued that the price at which the company was exporting the goods from Vietnam during the present POI is clearly suggestive of the price at which the company would dump from Vietnam in case of cessation of anti dumping duty.
30. It has been further argued that producers of subject goods in subject countries maintain huge capacities. Quoting certain news reports the Domestic Industry has submitted that Ritek maintains a capacity of about 20 Million Pcs per month in Vietnam alone. Quoting the information available in the website of Thai Trade Centre, a Govt. of Thailand (DITP) website, the domestic industry has submitted that the major Disc producer in Thailand i.e., Dyntech Disc Production Co. Ltd has a DVD manufacturing capacity of 0.8 Million per month. Jet Thai Hi-Tech Co. Ltd., another producer in Thailand and other countries, appears to have expanded its production base to Thailand as per its website report. It has been argued that given the global decline in demand for the product significant spare capacities are available in these countries to enable them to dump in significant quantities if the duties are revoked.
31. The petitioner domestic industry has further submitted that if the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping starts from another set of countries. This

shift in imports clearly shows that the importers are deliberately and consciously resorting to dumping and therefore, dumping will recur if duties are revoked.

G.2 Views of other interested Parties

32. No submission has been made on behalf of any other interested party with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping.

G.3 Examination by the Authority

33. The Authority notes that continuation of dumping has been established in case of import of DVD-R from Thailand and Vietnam as recorded in the previous section though the volume of imports from these countries has dropped significantly during the investigation period largely because of the anti-dumping duty imposed on several countries, including the subject countries. The anti-dumping duties have been extended on this product, originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei, on the basis of finding of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods from these countries and the duties are in force till 2019. However, a significant shift in imports from Vietnam to Taiwan has been noted in the post POI period which coincides with the reduction of duty on Taiwan in the sunset review against that country.
34. The Authority further notes that the demand for the product has seen a significant decline in the global market making some of the capacities in various countries surplus/idle. The domestic industry has provided certain information regarding available capacities in the subject countries, as recorded above, to establish that given the availability of spare capacities in these countries and decline in global demand there is a strong likelihood that the goods will be exported to India in dumped prices in bigger volumes.
35. No other interested party has placed any material fact before the Authority in this regard. Considering the fact that the dumping margins from the subject countries are still high though the volumes have declined and there is a clear indication of shift in volumes from countries as indicated above and keeping further in view that there is a significant demand supply mismatch in the global market for this product the Authority is of the view that there is a clear and imminent likelihood of increase in volume of dumped imports from the subject countries if the duties are revoked.

H. Determination of Injury and Causal Link; and Likelihood of Continuation or recurrence of Injury to the domestic industry

H.1 Legal Position

36. As stated in the previous section, in a sunset review investigation, with regard to injury examination the Authority is required to examine:
- Whether the domestic industry continues to suffer injury due to dumped imports and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are revoked; or
 - In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.
37. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries. Thereafter, the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject countries has been examined. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the manner as laid down under Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

H.2 Examination of Current injury to the domestic industry and Causal Links

H.2.1 Submissions by the domestic industry

38. The domestic industry has *inter alia* made the following submissions with regard to the injury and causal link:
- i. Current volume of imports from subject countries is low due to anti-dumping duty. If the present anti dumping duty is allowed to cease, flood gates will open up for these countries and the domestic industry would once again suffer significant injury. This gets clearly established by (a) the shifting pattern of imports from Vietnam prior to review and revision of anti-dumping duty, (b) significant dumping in the

product, (c) significant price undercutting in respect of the product, (d) significant capacities with the subject producers, (e) significant current exports from the subject countries, etc.

- ii. That there is continued dumping of the product under consideration from Thailand and Vietnam, though the volume of dumped imports has declined as a result of current anti-dumping duties. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from these countries should the current anti-dumping duty be revoked.
- iii. Domestic industry is suffering injury both from dumping from present sources as also some decline in demand. While it is appreciated that the decline in demand has been partly responsible for the decline in production and sales, the presence of dumped from these countries has aggravated injury to the domestic industry. Further and more importantly, the price at which the domestic industry is forced to sell the product under consideration in the market is clearly because of dumping of the product under consideration in the Country
- iv. Price undercutting is significantly positive in respect of DVD-R without anti-dumping duty. This indicates that the imports are undercutting the prices of the domestic industry and in the event of revocation of existing duties, the subject imports from the subject countries will undercut domestic prices to a significant degree
- v. Given the price difference between the imported and domestic price, the cessation of anti-dumping duty would lead to significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market
- vi. The domestic industry has reduced the capacity in view of tapering of global demand for the product and to retain its competitiveness. The production of the domestic industry has declined over the period. Domestic industry has been regulating production considering the demand for the product in the domestic and global market. The domestic sales of the domestic industry showed the same trend as that of production and have declined since base year.
- vii. The domestic industry is continually running into financial losses with respect to domestic sales. Further the domestic industry is facing continued negative return on capital employed which has deteriorated significantly in the POI.
- viii. With dumped imports likely to enter the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, would be left with no option but to sell the goods at still lower prices. Further, the domestic industry would be prevented from raising its prices in proportion to increase in costs. The domestic industry shall suffer increased financial losses.
- ix. Market share of the domestic producers as a whole has remained in similar region. In the event of revocation of the existing duty, the volume of imports from the subject countries will increase and capture the market causing further injury to the domestic industry
- x. The average inventory levels of the domestic industry have declined in period of investigation. This is due to the fact that the petitioner has regulated production in order to contain inventory levels.

H.2.2 Submissions by producers / exporters / importers and other interested parties

39. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions with regard to injury to the domestic industry.

H.2.3 Examination by the Authority

40. In the light of the various submissions made by the domestic industry the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of injury on account of dumped imports from the subject countries.
41. Rule 11 of Anti-dumping Rules, read with Annexure-II, provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of

such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

42. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II of the rules supra.
43. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.
44. The authority notes that the subject goods are at present attracting anti dumping duty from China, Hong Kong and Taiwan in addition to the subject countries. The authority has considered the volume and price impact of imports from all these countries along with other sources for determination of injury and causal link, including the likelihood scenario, if the anti dumping duties are withdrawn in respect of the subject countries. For the purpose of this review the injury to the domestic industry, on account of dumped imports of the subject countries, has been assessed cumulatively. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined to assess the impact of current dumping as follows:

(a) Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Import Volume & Share of the subject countries

45. To examine the volume and prices of dumped imports request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of import data of the subject goods for the injury investigation period. The Authority also notes that DGCI&S transaction-wise import data up to March 2014 was examined in detail and relied upon in its final findings dated 14th Oct 2014 in the sunset review investigation against China, Hong Kong and Taiwan. Therefore, for the purpose of the present investigation the same data has been relied upon for the overlapping period of the injury investigation. The present investigation covers the period upto Sept 2014. The domestic industry has also provided transaction-wise import data obtained by them from a secondary source i.e., International Trade Advisory Services (ITAS) for the POI (April 2013- Sep 2014) and has argued that this data includes certain transactions of imports at JNPT and Patparganj ICD during the period April 2014-Sept 2014 which are not reflected in the DGCI&S data. Therefore, for these additional transactions have been considered along with DGCI&S data as enumerated above for the purpose of this investigation. The data considered for this investigation have been placed in public folder. Accordingly, imports of the subject goods during the injury investigation period is as follows:

In Lac Pcs

| Particulars | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI | Post POI |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Imports –Volume | | | | | | |
| Subject Countries | 283.37 | 271.99 | 121.50 | 74.51 | 49.67 | - |
| Thailand | 78.44 | 13.60 | - | 52.50 | 35.00 | - |
| Vietnam | 204.93 | 258.39 | 121.50 | 22.01 | 14.67 | - |
| Countries attracting duties | 21.77 | 2.04 | 1.66 | 11.25 | 7.50 | 55.93 |
| China PR | 20.27 | 2.04 | 1.56 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| Taiwan | 1.49 | - | 0.10 | 10.50 | 7.00 | 54.93 |
| Hong Kong | - | - | - | - | - | - |
| Other Countries | 338.03 | 295.85 | 174.08 | 211.03 | 140.68 | 54.00 |
| Total Imports | 643.16 | 569.88 | 297.24 | 296.79 | 197.86 | 109.93 |

46. The above data indicates that total imports have declined by about 70% compared to the base years and the current volume of imports from the subject countries have also declined over the injury investigation period and is low in the POI. During Post POI period (October 2014- March 2015) there are no imports from subject countries. However, the data indicates that imports from Taiwan have increased significantly in the post POI. The petitioner

has argued that with enhancement of duty from Vietnam in the MTR and lower duty against Taiwan in the SSR, Ritek, having production facilities in both Vietnam and Taiwan, has started exporting the goods from Taiwan in increased volumes. Therefore, in the event of cessation of anti-dumping duty from Vietnam, the exports will resume from Vietnam.

47. The authority notes that anti dumping duties are in force against import of the subject goods from a number of countries and the import data above indicates that the imports from those countries also exhibit a steady decline except for Taiwan where the trend has reversed after reduction of the duties in the SSR against those countries.

ii. Demand and Market Share

48. The demand and market share of the domestic industry and the subject countries in the subject goods in India has been assessed taking into account the sales of the domestic industry and imports.

In Lac Pcs

| Particulars | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualised POI | Post POI |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|----------|
| Sales of Domestic Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | 100 | 99 | 82 | 72 | 72 | 46 |
| Sales of Other Indian Producers | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | 100 | 198 | 163 | 144 | 144 | 92 |
| Subject Countries | 283 | 272 | 122 | 75 | 50 | 0 |
| Countries already attracting duties | 22 | 2 | 2 | 11 | 8 | 56 |
| Other Countries | 338 | 296 | 174 | 211 | 141 | 54 |
| Trend | 100 | 88 | 51 | 42 | 42 | 32 |
| Total Demand | 6,681 | 6,965 | 5,563 | 7,252 | 4,835 | 1,601 |
| Trend | 100 | 104 | 83 | 72 | 72 | 48 |

49. The Authority notes that, during the period of investigation the demand for the subject goods have declined by about 28% compared to the base year. The domestic industry's sales have also declined by the same percentage during this period whereas other domestic producers have gained and increased their sales in the domestic market by about 44% in the same period. Total imports have fallen by 70% during this period. The decline in imports are apparently largely due to antidumping duties in force against a number of countries. In fact it appears that a part of the space vacated by the imports is being occupied by other domestic producers though their sales volumes are very small compared to the volume of sales of the domestic industry.

50. After examining the general trend in demands the Authority has examined the trend in market share of various players in the domestic market.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI | Post POI |
|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|-------------------|-------------|
| Sales of Domestic Industry | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 |
| Sales of Other Indian Producers | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 190 | 196 | 198 | 198 | 193 |
| Subject Countries | % | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 92 | 51 | 24 | 24 | 0 |
| Thailand | % | 1.17 | 0.20 | - | 0.29 | 0.29 | - |
| Vietnam | % | 3.07 | 3.71 | 2.18 | 0.31 | 0.31 | - |
| Countries already attracting duties | % | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.66 |
| China PR | % | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|
| Taiwan | % | 0.02 | - | 0.00 | - | - | 1.66 |
| Hong Kong | % | - | - | - | - | - | - |
| Other Countries | % | 5.06 | 4.25 | 3.13 | 2.64 | 2.64 | 2.13 |

51. The Authority notes that while the market share of the subject countries have declined significantly, the market share of the domestic industry for DVD-R has remained almost same over the injury investigation period. The market shares vacated by the other countries and countries attracting Anti dumping duty have been occupied by the other Indian producers. The volume of import of DVD-R from the subject countries and its market share during the injury investigation period is insignificant.
52. Therefore, there is no significant volume impact of the dumped imports on the domestic industry as the cumulative imports from the subject countries are very insignificant and there is a significant decline in the domestic demand. However, the authority notes that this being a sunset review investigation the volume of import during the injury investigation period is not relevant and may not give a true picture of the likely situation of imports and condition of the domestic industry in the event of revocation of the duty.

(b) Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

53. The impact of the dumped imports of the subject goods from the subject countries on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of dumped imports of subject goods from the subject countries.
54. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The Authority has worked out the non-injurious price for the domestic industry as per annexure-III to the Rules and compared the same with the landed values of imports from the subject countries to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry as per its consistent practices by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

i. Price Undercutting

55. Since antidumping duties are in force the price undercutting effects of the dumped imports from the subject countries has been analysed by comparing the domestic selling prices with the landed values of imports from the subject countries with and without antidumping duties to see the impact, if any. The price undercutting works out as follows:

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Price undercutting without Anti-dumping duty | | | | | |
| Landed price of subject countries | Rs/Pc. | 3.73 | 3.46 | 3.94 | 4.40 |
| Trend | | 100 | 93 | 106 | 118 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 112 | 116 | 111 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 150 | 136 | 98 |
| Price Undercutting (%) | % | *** | *** | *** | *** |
| Price Undercutting | % Range | 30-40 | 40-50 | 35-45 | 25-35 |
| Price undercutting with Anti-dumping duty | | | | | |
| Landed price of subject countries | Rs/Pc. | 5.05 | 4.88 | 5.57 | 6.04 |
| Trend | | 100 | 97 | 110 | 120 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 112 | 116 | 111 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 242 | 164 | 43 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------|------|
| Price Undercutting (%) | % | *** | *** | *** | *** |
| Price Undercutting | % Range | 5-15 | 20-30 | 10-20 | 0-10 |

56. The Authority notes that the landed value of dumped imports of DVD-R from the subject countries has been significantly below the selling prices of the petitioner domestic industry. Even duty paid landed values are significantly undercutting the prices of the domestic industry during the entire injury investigation period though the volume of imports continued to be low.

ii. Price Suppression / Depression effects of the dumped imports

57. To examine the price suppression or depression effects of the dumped imports from subject countries on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values of imports from the subject countries, with and without antidumping duties, to examine if the prices were suppressed or depressed to any significant degree.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Cost of sales - Domestic | Rs/Pcs | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>109</i> | <i>136</i> | <i>145</i> |
| Selling price - Domestic | Rs/Pcs | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>112</i> | <i>116</i> | <i>111</i> |
| Landed price without ADD | Rs/Pcs | 3.73 | 3.46 | 3.94 | 4.40 |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>93</i> | <i>106</i> | <i>118</i> |
| Landed price with ADD | Rs/Pcs | 5.05 | 4.88 | 5.57 | 6.04 |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>97</i> | <i>110</i> | <i>120</i> |

58. The above data indicates that while the cost of sales of the domestic industry has increased significantly since 2012-13 because of lower capacity utilisation and other factors, their domestic selling prices have remained low and significantly below the cost of sales. The import prices have increased moderately during this period by about 18-20%. Since the cost increase is partially due to factors such as low capacity utilisation and depreciation etc. the increase in cost due to these factors has been isolated and the data has been examined to see whether the prices have been suppressed or depressed due to the presence of dumped imports. The selling price has been found to be below the normated cost for the POI indicating that the prices are suppressed due to various factors such as demand decline and presence of dumped imports undercutting the domestic prices.

iii. Price underselling effects of dumped imports

59. To examine the price underselling effects of the dumped imports, if any, the Non-Injurious price of the product for the domestic industry has been compared with the landed values of imports from the subject countries (with and without antidumping duties) as follows:

| Particulars | Unit | Thailand | Vietnam | Thailand | Vietnam |
|---------------------|--------------|-------------|---------|----------|---------|
| | | Without ADD | | With ADD | |
| Non Injurious Price | US\$/000'Pcs | *** | *** | *** | *** |
| Landed Price | US\$/000'Pcs | 71.61 | 73.96 | 97.59 | 103.72 |
| Injury Margin | US\$/000'Pcs | *** | *** | *** | *** |
| Injury Margin | % | *** | *** | *** | *** |
| Injury Margin | % Range | 55-65 | 50-60 | 15-25 | 10-20 |

60. The above data shows that the landed value of imports of DVD-Rs from the subject countries has been lower than the non-injurious price of DVD-R of the domestic industry during the POI even after application of antidumping duty on such imports thereby showing significant price underselling effects. The underselling margins even with application of duty are significant.

H.3 Examination of other economic parameters of the domestic industry

61. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

62. The various injury parameters as above relating to the domestic industry have been examined as follows:

a. Actual and potential impact on capacity, production, capacity utilization and sales

63. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Capacity | Lac Pcs | 18,921 | 18,889 | 18,892 | 26,492 | 17,662 |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>93</i> | <i>93</i> |
| Production | Lac Pcs | *** | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>93</i> | <i>75</i> | <i>57</i> | <i>57</i> |
| Capacity Utilization | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>93</i> | <i>75</i> | <i>61</i> | <i>61</i> |
| Domestic Sales Volume | Lac Pcs | *** | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>99</i> | <i>82</i> | <i>72</i> | <i>72</i> |

64. The above data indicates that the domestic industry has rationalised its capacities marginally in the POI. However, the production have fallen significantly during the POI by about 43% thereby affecting the capacity utilization, which has fallen below 50% in period of investigation from a level of above 75% in the base year. The decline in production is because of decline in domestic sales, which has fallen by about 28% from the base year and also because of decline in export sales which has fallen significantly during the injury investigation period apparently due to decline in global demand for the product.

b. Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, return on capital employed

65. Financial performance of the domestic industry with respect to the product under consideration has been examined in terms of the above parameters as follows:

| Particulars- | Units | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI Annualized |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| Net profits/(loss) | Rs.Lacs | (***) | (***) | (***) | (***) |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>-100</i> | <i>-85</i> | <i>-205</i> | <i>-248</i> |
| Net profits/(loss) | Rs per Pcs | (***) | (***) | (***) | (***) |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>-100</i> | <i>-86</i> | <i>-251</i> | <i>-346</i> |
| Cash profits | Rs. Lacs | *** | *** | (***) | (***) |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>143</i> | <i>-54</i> | <i>-324</i> |
| Return on capital employed | % | (***) | (***) | (***) | (***) |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>-100</i> | <i>-84</i> | <i>-346</i> | <i>-761</i> |

66. The above data indicates that though the petitioner domestic industry was earning cash profit in its domestic sales of the subject goods upto 2011-12 the cash profit on domestic sales have become significantly negative thereafter because of significant increase in costs without commensurate increase in prices in the domestic market. The net profit has remained negative throughout the injury investigation period and the losses have increased since 2012-13. As noted earlier the increase in costs over this period is due to significant decline in production because of demand decline and other factors, and the domestic industry has not been able to increase the prices due to the presence of dumped imports from several sources, including the subject countries, though the volumes remain low. The return on capital employed has remained negative in the entire injury investigation period and has worsened further during the POI.

c. Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, return on capital employed

67. Other physical parameters of the domestic industry have been examined as follows:

| Particulars- | Units | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI Annualized |
|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| Inventory | Lac Pcs | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>77</i> | <i>62</i> | <i>51</i> |
| Number of employees | Nos | 1,692 | 1,950 | 1,986 | 993 |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>115</i> | <i>117</i> | <i>59</i> |
| Productivity per employee | Lac Pcs | 8.78 | 7.09 | 5.57 | 3.74 |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>81</i> | <i>63</i> | <i>43</i> |
| Wages | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | <i>Indexed</i> | <i>100</i> | <i>118</i> | <i>123</i> | <i>49</i> |

68. The above data indicates that there is a diminishing trend in the inventory built up of the domestic industry as the petitioner has regulated production in order to contain inventory levels. However, In spite of reduction and rationalisation of employment due to reduction in capacity and production, the productivity has fallen as the capacity utilisation has fallen below 50%.

I. Causal Link

69. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. In the absence of any argument put forth by any other interested party the Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry. The following issues have been brought to the notice of the authority by the domestic industry and have been examined as per information available for the non-attribution analysis:

i. Import from other countries

70. The Authority notes that though the subject goods are being imported from several countries other than the subject countries the imports from some of these countries are either negligible or already attracting duty. There are significant imports from UAE. But these imports are at higher prices. However, total import to the country from other sources has significantly declined during the injury investigation period. Therefore, imports from other sources are not a factor affecting the domestic industry.

ii. Contraction in Demand

71. The Authority notes that there has been a continuous decline in demand of the products in the domestic market as well as global market. While recognising the fact that decline in global demand which affects the production and sale of the domestic industry as well, the Authority, in its previous finding dated Oct 2014, noted that though there is a decline in demand for DVDs in India in the last few years, which is on the line of global trends, DVDs would continue to remain the preferred medium for data storage and transmission for some time to come and therefore, cannot be considered as the major reason for the injury caused to the domestic industry.
72. The domestic industry, in its submissions, has argued

- That though the demand for the product under consideration has declined in the global market due to availability of competing and new technology products such as USBs/pen drives and other data storage devices such as blue rays and other internet platforms for entertainment related requirements, the DVD-Rs as a storage media device continues to have significant utility and for at least another ten years. The domestic industry has further argued that though there are various option available for data storage and transmission, per GB cost of storage and transmission through various media would still make use of DVD-Rs more viable and attractive option for some time to come and in fact these products are being used in certain segments more widely and new areas such as Photo storage, medical diagnostics, are emerging and demand in movies and games etc. continues. The domestic industry has presented a comparative cost analysis and usage of various storage and transmission option to justify its claim as follows:

| Product | Market price Rs/Pc | Per GB Cost Rs/Pc | Usage | Remarks |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| CDR | 8.5 | 12 | One time storage | Largely getting substituted by DVDR Cheaper than DVDR. So, still some use |
| CDRW | 15 | 21 | Multiple time storage | Largely getting substituted by DVDRW Cheaper than DVDRW. So, still some use |
| DVD-R | 15 | 3 | One time storage | Continues to have significant decline Demand continues in rental movies and games Demand increased in photo segment medical diagnostics Sale of DVD players shows increase → present and potential demand for DVD-R |
| DVD-RW | 40 | 10 | Multiple time storage | Easy transportability More expensive for one time storage and transmission as compared to DVD-R Less expensive for one time storage and transmission as compared to DVD-R |
| Blue Ray | 150 | 6 | Multiple time storage | Easy transportability Expensive for one time storage and transmission |
| Pen-drive | 200 | 25 | Multiple time storage | Easy transportability Expensive for one time storage and transmission Demand not increasing so significantly |
| Internet with cloud | | 74 | Downloading, viewing, transmission, & storage | Low penetration of internet in India (17%) Cloud usage is even below 5% Not available to masses Requires computer and knowledge Less transportability Expensive |

- That demand of DVD is still significant in developed nations where the access to internet is widespread. Hence, it was submitted that DVD demand would remain significant in India in the coming years. As regards internet, as per information publicly available, the penetration of internet in the Country at 17% is so insignificant even today that it cannot be concluded that internet would prove to be a death knell for DVD-R. Physical media like DVD still generate more movie revenue than streaming services. Demand for physical media would remain significant due to reasons like obsessive needs of collectors, for gifts and games. Only 9.5% of the population in India owns a computer or a laptop and only 3.1% of the Indian population owns computer/laptop with internet. Therefore, as claimed by the domestic industry the usage of pen drives or hard disk or internet downloading is limited to these numbers only. DVDs are also more prevalent where large data needs to be distributed to large number of people at economical cost as providing DVD costing Rs.15-20 is cost effective rather than pen-drive which costs about Rs. 200 or more.

- That USB/Pen drives are used only in those applications where a consumer has to write contents multiple times. Use of USB/Pen drive in those applications instead of DVD- R, where the consumers would write only once, is a gross underutilization of a pen drive. DVD-R is much more cost effective as it costs only Rs. 15 (to the end consumer) as compared to a pen drive typically costing more than Rs. 200. It has been submitted that Pen drive is essentially required for frequent/multiple storing of data/contents. Therefore, USB/Pen-drive as a storage medium cannot substitute DVD-R market.
 - That DVD-R presents a very good data storage platform for archival purpose for software, entertainment materials, etc which does not require multiple writing. Penetration of computer and internet is insignificant to lead to sharp decline in demand for DVD-R in this usage segments. New and emerging areas such as medical diagnostics, photo-storage, etc. would create new demands for DVDs.
 - That as regards Cloud Storage, the usage of which is even lower at 5%, the cost per GB is estimated in the region of Rs. 74 per GB, and therefore this option is highly expensive, not at all cost effective and luxurious. Therefore, it is being used only by those consumers who are not at all cost conscious. However, as the data would show it is just impossible that this kind of demand for DVD-R can be taken away by theoretically possible options such as cloud storage. It means incurring a cost of about Rs. 4000 crores for applications which can be served by DVD-R by incurring a cost of Rs. 170 crores. There is absolutely no commercial substitutability between the two.
 - That the most prominent sector where demand of DVD-R is high is the entertainment sector which includes rental movies, games, etc, which has not been penetrated by Blue Ray and Pen Drives despite their higher capacity. Emerging sectors include the medicine and hospital sector along with photography.
 - That the above indicates that though there is a decline in demand for DVDs in India in the last few years, which is on the line of global trends, DVDs would continue to remain the preferred medium for data storage and transmission for some time to come.
73. This issue has been examined in the context of non-attribution analysis to see whether the decline in the demand in the country and overall global demand is due to advent of other technologies and therefore, a cause of injury to the domestic industry as follows:
- An analysis of demand supply scenario of the storage devices as per public available information from various sources indicates that the global recordable/re-recordable disc production which stood at 12.3 bn discs in 2012 has declined to 9.9 bn discs in 2015 and DVD-R production, which stood at 6.3 bn discs in 2012 has declined to 5.1 bn. However, the share of DVD-R in the total recordable/re-recordable disc production has increased from 49% to 51% (Futuresource Consulting Ltd.). The projection for global recordable optical disc market is to reach 4.224 bn units by 2025. The report further stated that awareness about data security and storage are expected to boost the demand for these products.
 - As per CMR Report though the optical disc market in India is shrinking by about 9.6% CAGR (2012-16), the DVD-R market is still going strong, maximum decline being in the CD-R segment. The report also suggests that the consumption in photo segment, hospital diagnostic segment is increasing. The import of significant volume of DVD players into India in the recent years implies that there is still significant demand for the product which will continue to remain for at least next 5 to 10 years.
74. The above examination indicates that though demand for DVD-Rs as storage media devices is declining there is still substantial demand for the product and the product will continue to have significant global presence for some time to come. The performance of the domestic industry has been adversely affected by this decline as the petitioner industry has significant domestic as well as export sales of the subject goods. But the question is whether the current decline in performance of the domestic industry can be fully attributed to the demand decline alone.
75. The Authority notes that the petitioner domestic industry carries significantly high capacities for production of the subject goods and had major share in domestic as well as export market. These capacities were created at a time when the demands for these products were high and there was a reasonable expectation of good domestic and global market for the product. The production at present is below 50% of the capacity and the domestic demand now is about 25% of its total capacity though its export sales historically accounted for above 50% of its total sales. Both

the domestic and global market show declining trend though in absolute term there is still significant demand in the domestic market as well as global market which can be catered to by the petitioner if the prices are right.

76. Therefore, it appears that while the decline in demand has majorly affected the physical performance of the petitioner domestic industry, continued presence of dumped imports from various sources has further aggravated the situation as it has prevented price rationalisation to recover its costs. Therefore, demand situation alone cannot not be attributed to the injury suffered by the domestic industry.

iii. Pattern of consumption

77. The pattern of consumption of DVDs *vis-a-vis* other competing products as discussed in the previous section indicates that though there is certain changes in the consumption patterns there is still significant consumption and demand for the DVD-Rs in India and shall continue for a significant period. Therefore, change in consumption pattern cannot be fully attributed to the injury suffered by the domestic industry.

iv. Conditions of competition:-

78. The petitioner domestic industry is the dominant player in the domestic market and other producers have very small market share. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the injury to the domestic industry.

v. Developments in technology:-

79. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology in the manufacturing process or usage of the product except for the arrival of new technology and competing products such as pen drives, blue-rays and internet based transmission as discussed in para (ii) above, which could have caused injury to the domestic industry.

vi. Export performance of the domestic industry: -

80. The volume of exports of the domestic industry has declined significantly during the injury investigation keeping in line with the global trend and this has added to the injury of the domestic industry in terms of decline in production and capacity utilisation.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----|-------------------|
| Export | Lac Pcs | *** | *** | *** | *** | *** |
| Trend | | 100 | 103 | 62 | 132 | 67 |

81. However, the injury analysis in the previous section is based on the domestic performances of the domestic industry which is affected by the dumped imports. Prices and profitability in the domestic and export markets have been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry. Therefore, though decline in export performance has contributed to the injury, the injury suffered by the domestic industry on account of its export performance has not been attributed to the dumped imports.

J. Conclusion on current Injury and causal Links

82. The above examination of various injury parameters and non attribution factors for establishing the causal links between the dumping and injury indicates that the petitioner domestic industry has suffered injury in terms of loss in production and sale, decline in capacity utilisation, increase in losses and negative return on capital employed. The injury is significant and material. However, the volume of imports from the subject countries being too low at the moment the volume impact of dumped imports does not seem to be significant or material at present. The landed values of DVD-Rs imported from the subject countries continue to significantly undercut the prices of the domestic industry and also have underselling effect on the domestic industry's selling prices though the volume is low. On the other hand examination of demand scenario and capacities indicates that the said injury is substantially due to decline in the domestic as well as global demand for the product during the injury investigation period though the presence of dumped imports have aggravated the situation by way of preventing price increase in the domestic market to a remunerative level so as to enable the industry increase its production and sale to bring down the cost. Therefore, the Authority concludes that while the current dumped imports are not the principal cause of the

injury suffered by the domestic industry at present, it has, through its price effects, not enabled the industry to improve its performance and recover.

K. Likelihood of continuation or recurrence of injury

83. The Authority notes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of injury if the duties are to be removed, even if there is no current injury and/or causal link. In the previous section on likelihood of continuation or recurrence of dumping it has been established that dumping is likely to continue or recur from the subject countries in the event of withdrawal of the duties. It has also been established that the domestic industry continues to suffer material injury though said injury is not proximately on account of the dumped imports. Therefore, the Authority has examined whether the injury would continue or intensify if the duties are revoked.

K.1 Submissions by the domestic industry

84. The petitioner has claimed that the cessation of anti dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. It has been further claimed that the entire purpose of the review investigation is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such duty, dumping would continue or recur; and whether the domestic industry would continue to suffer material injury or the injury to the domestic industry would recur if duties are removed. In this regard the petitioner has stated the following:
- a) Subject imports of DVD-R are undercutting the prices of the domestic industry in the absence of duties. Cessation of present anti dumping duty is likely to have significantly adverse effect on the prices of the domestic industry in the market.
 - b) Continued adverse performance of the domestic industry shows likelihood of further deterioration in profits and return on capital employed in the event of cessation of anti dumping duties. Thus, cessation of present anti dumping duties is likely to lead to further deterioration in performance of the domestic industry.
 - c) Presence of dumped imports in the Indian market continues to be significant. Even though the present volumes are low, the volume is likely to increase significantly in the event of cessation of anti dumping duties.
 - d) Continued presence of dumped imports in the Country is preventing the domestic industry from charging fair price for the domestic industry. The price underselling being faced by the domestic industry is because of dumped imports.
 - e) Growth of the domestic industry became negative in respect of a number of parameters. Under the circumstances, the growth shall become further negative in the event of cessation of anti dumping duty.
 - f) The domestic industry is currently suffering from the effects of dumping of the subject goods. In the event of cessation of anti-dumping duties on imports from subject countries, injury to the domestic industry will not only continue but also intensify.
 - g) If the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping starts from other set of countries. This shift in imports clearly shows that the exporters are deliberately and consciously resorting to dumping to retain their market shares in global market due to over capacities in those countries.
 - h) The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration. If the price undercutting is examined cumulatively from various dumped sources it would be seen that the weighted average price undercutting by dumped imports is significantly positive. Given the nature of the product under consideration, it is obvious that the producers in subject countries are unlikely to get a price different from the prices at which other foreign producers are exporting the product under consideration. Thus, the price undercutting from imports from other countries is a clear indicator of the price undercutting that is likely from the subject countries in the event of cessation of anti dumping duties.

- i) There is a strong likelihood of dumping and consequent injury as there is a global decline in demand for DVD. Since global demand for DVD has been declining, cessation of anti dumping duty on imports from the subject countries shall provide easy access to the producers in these countries to the vast Indian market while the demand is shrinking elsewhere since absolute demand for DVD in the Indian market still continues to be significant.
- j) The petitioner is already suffering material injury in terms of all parameters. Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from subject countries in the market would definitely cause an adverse impact over the Domestic Industry.
- k) It is not necessary that all conditions should exist for continuation of duty. There are numerous cases wherein the duty has been continued even when one or more parameters were satisfied.
- l) Even in the event of low volumes of imports reported during the POI of a sunset review investigation, anti-dumping duty can be continued. There are a number of instances where foreign authorities have continued the duty in the first and subsequent sunset reviews.
- m) India has extended anti dumping duties on a number of products despite low volume of imports. The illustrative cases in this regard includes zinc oxide, Sodium Hydrosulphide, Duct Tile Iron Pipe, Front Axel Beam & Steering knuckles, Fully Drawn Yarn, Potassium Permanganate to name a few.
- n) Therefore, there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent continuation of injury to the domestic industry. Therefore, the Authority should continue the duty.

K.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

85. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

K.3 Examination by the Authority

86. The Authority has looked into the current volume and value of imports of the subject goods from the subject countries as well as other countries and the volume of domestic sales of the domestic industry to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty. The Authority notes that the current imports volumes are low from the subject countries as well as other countries. The Authority also notes that a clear likelihood of continuation/recurrence of dumping has been established in the previous section based an objective examination of various factors. Accordingly, the following factors have been examined to see if there is any imminent likelihood of continuation or recurrence of injury:

a) Level of current and past dumping margins

87. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation for DVD-Rs is significant though the volume of import during the POI from the subject countries is low. However, the Authority notes that antidumping duties on the subject countries, as well as few other countries, have been successful in preventing large scale dumped imports from these countries though these countries have significant spare capacities. Authority further notes that despite the domestic industry holding the capacity to meet the entire demand, significant volume of import is taking place from several countries at much lower prices. Therefore, there is a very high possibility that once the duties are removed imports will start from these countries at comparable prices. At these prices the price undercutting and underselling to the domestic industry prices will be significant preventing it to recover even the normated non-injurious price. Therefore, injury to the domestic industry, which still continues to suffer injury because of several factors, including dumping, is likely to be intensified.

b) Price attractiveness of Indian market

88. The prices at which the subject goods are being exported from the subject countries to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is positive undercutting even after taking into account applicable anti-dumping duty on the product. Thus, with the revocation of anti-dumping duty, the Indian market would be too attractive for the producers in the subject countries to intensify their exports to India at marginal cost prices and there is strong likelihood that Indian consumers would

resort to large scale imports of the subject goods from the subject countries leading to intensification of injury to the domestic industry.

c) Global demand – supply scenario

89. There is a clear demand supply mismatch in the global DVD market, capacities exceeding the demand on the face of competing technologies. Therefore, there is clear possibility of aggressive market entry strategies being applied by global players and intensified dumping in India if duties are removed and the price level will be dictated by their market entry strategies leading to severe price undercutting and underselling which will further affect the domestic industry's capacity utilisation and profitability.
90. The petitioner domestic industry holds significant capacities for domestic as well as export sales. While the demand decline has significantly affected the production and sales and contributed to the injury suffered, the domestic market share and price plays a significant role in the survival of the industry. Therefore, if the duties are revoked the petitioner domestic industry is likely to lose significant share to the imports from the subject countries and the injury is likely to be intensified.

L. Post disclosure submissions of the interested parties

91. The disclosure statements were sent to the domestic industry and the embassies of the subject countries for their comments, if any. No comment has been received from any interested party other than the domestic industry. The domestic industry, in its comments have essentially re-iterated its position with regard to the demand scenario and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and has requested for continued imposition of the duties in fixed term and dollar denominated.

M. Magnitude of Injury and injury margin

92. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry, as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules, has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as follows:

| Particulars | Unit | Thailand | Vietnam |
|---------------------|--------------|----------|---------|
| Non Injurious Price | US\$/000'Pcs | *** | *** |
| Landed Price | US\$/000'Pcs | 71.61 | 73.96 |
| Injury Margin | US\$/000'Pcs | *** | *** |
| Injury Margin | % | *** | *** |
| Injury Margin | % Range | 55-65 | 50-60 |

N. Conclusion on injury and Likelihood of injury

93. In conclusion the Authority notes that the subject goods from the subject countries continue to enter the Indian market at dumped prices which significantly undercut the prices of the domestic industry even if the present antidumping duty on them is taken into consideration to calculate the landed values. The import prices are also significantly below the fair price or the non-injurious price determined for the petitioner domestic industry after removing all abnormal costs as per the consistent practice of the Authority. Given the current global demand scenario and the projections as recorded in the previous section and the capacities available in these countries there is a clear likelihood of continuation or intensification of dumping when these producers compete to keep their production lines operational at marginal cost prices. If the said trend continues the prices will continue to significantly undercut the domestic industry's prices once the duty protection is removed and that would prevent any price recovery for the domestic industry. If the prices in the domestic market do not recover the domestic industry would not be able to improve and rationalise its production to bring down the costs and the losses will increase.
94. The domestic industry carries significant capacities at the cost of significant investment. The demand situation, as analysed in the previous situation, indicates that though the product is on decline or phase out curve, there shall be significant demand for the product in absolute term for at least next 5-10 years which can be catered to by the domestic industry with some rationalisation of the capacities. However, if the duties are revoked the production and

sales volume will further fall and make the production completely unviable as the current prices of dumped imports without duty element would be less than the variable costs of the domestic industry and imports are likely to increase significantly as the market still exists. Therefore, there is a clear and imminent likelihood of continuation and intensification of the injury suffered by the domestic industry if the duties are revoked.

O. Indian industry's interest & other issues

95. No argument has been put forward by any interested party regarding the interests of the users and other such interested parties. However, the Authority notes that the subject goods are consumer goods directly used by entertainment and IT industry and public at large which may be affected by continuation of the duties. The Authority further notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of free and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. On the other hand, if distortion caused by the dumped imports are not corrected it may lead to closure of the domestic production base and subsequent price increase by the foreign producers, which will adversely affect the users interests in short as well as long term.

P. Recommendations

96. The Authority initiated and conducted the investigation into current dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty in terms of the Rules laid down. It has been clearly established in the foregoing paragraphs that there is a clear and imminent likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries, in the event of withdrawal of duty.
97. It has also been established that the domestic industry is likely to continue to suffer material injury and the injury would intensify if the duties are removed. Therefore, there is a need for continued imposition of the duties to protect the domestic industry against continuation / recurrence of dumping from the subject countries and continuation/ recurrence of injury to the domestic industry.
98. In the factual matrix of the case and keeping in view the current dumping and injury margins of DVD-Rs and DVD-RWs the Authority is of the view that there is a need to extend the duties on DVD-Rs originating in or exported from the subject countries.
99. Therefore, the Authority recommends continuation of duty, on the subject goods originating in or exported from the subject countries as per the dumping and injury margins calculated for the investigation period, for a further period of 5 years from the date of its imposition to prevent recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established for DVD-Rs, originating in or exported from the subject countries so as to remove the injury to the domestic industry.
100. The duties, arising out of the previous investigation, were imposed in terms of fixed duties. Accordingly, the Authority recommends continued imposition of definitive antidumping duties equal to the amount indicated in Column-9 of the table below from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of DVD-Rs originating in or exported from the subject countries for a further period of 5 years.

Duty Table

| Sl. No | Sub Heading or Tariff Item | Description of Goods | Specification | Country of origin | Country of Export | Producer | Exporter | Duty Amount | Unit of Measure | Currency |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 8523 | Digital Versatile Discs, Recordable | DVD-R, DVD+R, and mini DVD-R | Vietnam | Any | Any | Any | 41.35 | Per 1000 pieces | USD |
| 2 | -Do- | -Do- | -Do- | Any country other than the subject countries and | Vietnam | Any | Any | 41.35 | -do- | -do- |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|----------|-----|-----|-------|------|------|
| | | | | countries attracting antidumping duty under any other Notification | | | | | | |
| 3 | -Do- | -Do- | -Do | Thailand | Any | Any | Any | 43.70 | -do- | -do- |
| 4 | -Do- | -Do- | -Do | Any country other than the subject countries and countries attracting antidumping duty under any other Notification | Thailand | Any | Any | 43.70 | -do- | -do- |

Note

Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column "Country of Origin".

Q. Further Procedures

101. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
102. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and the Rules, and Public Notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority